लखनऊ

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

गुरुवार, 23 जुलाई, 2026
वर्ष : 11 । अंक: 325
मूल्य : 1 रुपये
पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। — स्वामी विवेकानंद

TODAY WEATHER

DAY 32° Hi
NIGHT 28° Low

संक्षेप

'चेस्ट' और 'ब्रेस्ट' में फर्क बेमानी, हाई कोर्ट ने पास्को एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न पर सुनाया अहम फैसला

कोच्चि। बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों (पॉक्सो) को लेकर केरल हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ कर दिया है कि पॉक्सो एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न के मामलों में 'चेस्ट' (छाती) और 'ब्रेस्ट' (स्तन) के बीच का अंतर पूरी तरह से निराधार और बेमानी है। अगर कोई व्यक्ति यौन मंशा के साथ किसी बच्चे की छाती को पकड़ता या छूता है, तो उसे कानूनी तौर पर यौन उत्पीड़न ही माना जाएगा। यह सख्त और स्पष्ट टिप्पणी 12 साल के एक लड़के के यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई के दौरान आई है, जिसने कानूनी शब्दों की आड़ में बचने की कोशिश कर रहे आरोपियों को एक कड़ा संदेश दिया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष (सरकार) का आरोप था कि आरोपी ने गलत (यौन) नीयत से बच्चे को पीछे से पकड़ा था। इसके बचाव में आरोपी ने अदालत में अजीबोगरीब दलील दी कि किसी बच्चे की 'छाती' (चेस्ट) को महज छूना या पकड़ना पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आता। उसका तर्क था कि केवल यौन मंशा से 'ब्रेस्ट' को छूने पर ही यह अपराध बनता है। इस पर अदालत ने दोनों शब्दों के अर्थ और अंतर को गहराई से परखा। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में स्पष्ट किया कि भले ही मेडिकल और शारीरिक संरचना के आधार पर इन दोनों शब्दों के अलग-अलग मायने होते हों, लेकिन यौन उत्पीड़न के मामलों में 'चेस्ट' का इस्तेमाल आमतौर पर 'ब्रेस्ट' के पर्यायवाची के रूप में ही किया जाता है। इसलिए, ऐसी हरकत को हर हाल में यौन हमला ही माना जाएगा।

नीट को हमेशा के लिए खत्म करो, थलपति विजय की पार्टी ने कर दी बड़ी मांग

चेन्नई। नीट परीक्षा में हुए पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में मचे बवाल के बीच अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय भी छात्रों के समर्थन में खुलकर मैदान में आ गए हैं। तमिल सिनेमा के 'थलपति' और अब सूबे के मुखिया विजय की पार्टी तमिझगा वेत्री कज़गम ने नीट परीक्षा को लेकर एक ऐसी मांग कर दी है, जिसने सियासी पारे को और भी ज्यादा चढ़ा दिया है। अ्क्ष्रय ने दो टूक कहा है कि नीट में धांधली रोकना ही काफी नहीं है, बल्कि इस पूरी प्रवेश परीक्षा को ही हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर देना चाहिए। छात्रों के भविष्य और राज्यों के अधिकारों का हवाला देते हुए अ्क्ष्रय ने संविधान में बड़े बदलाव की वकालत की है। पार्टी का स्पष्ट मानना है कि इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची से हटाकर राज्य सूची में ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए। पार्टी ने यह भी सुझाया है कि अगर ऐसा करने में कोई कानूनी अड़चन आती है, तो अंतरिम उपाय के तौर पर एक 'विशेष समवर्ती सूची' बनाई जाए। इससे राज्य सरकारों को मेडिकल एजुकेशन पर पूरा अधिकार मिल सकेगा। पार्टी ने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री विजय पहले ही इस समाधान की रूपरेखा तय कर चुके हैं। इस मुद्दे पर अ्क्ष्रय ने राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी ष्टरूय पर भी जमकर निशाना साधा। अ्क्ष्रय ने तंज कसते हुए कहा कि उनकी पार्टी छात्रों और जनता के साथ धोखे की राजनीति नहीं करती है।

काले कपड़ों में संसद पहुंचे विपक्षी सांसद, छात्रों के मुद्दों पर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

नई दिल्ली, एजेंसी। छात्र प्रदर्शनकारियों और सांसदों के साथ कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में बुधवार को विपक्षी दलों के कई सांसदों ने संसद पहुंचकर काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सांसद इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार छात्र आंदोलनों और देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को ठीक तरीके से नहीं संभाल रही है। प्रदर्शनकारियों ने मकर द्वार के सामने एकजुट होकर अपना विरोध दर्ज कराया।

कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा कि काले कपड़े पहनने का फैसला मंगलवार को हुए प्रदर्शन के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य सांसदों के साथ पुलिस की कथित सख्ती के विरोध में लिया गया है। उन्होंने कहा, 'आज हम सभी काले कपड़े पहनकर आए हैं, क्योंकि हम मकर द्वार के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन कल विपक्ष के नेता और अन्य सांसदों के साथ पुलिस द्वारा की गई कथित बर्बर कार्रवाई के खिलाफ है।'

आरजेडी सांसद संजय यादव ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में बार-बार पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं और बेरोजगारी पिछले 50 वर्षों के सबसे ऊंचे स्तर पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि पारदर्शिता की मांग कर रहे युवाओं पर सरकार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। यादव ने कहा कि सरकार की खराब नीतियों के कारण करोड़ों छात्र और युवा बेरोजगार हैं और उनका भविष्य अनिश्चित हो गया है।

10 साल में 152 पेपर लीक, एक को भी सजा नहीं: राहुल

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने एक वीडियो चलाया। उसमें पुलिस छात्रों पर लाठी चार्ज कर रही थी। इसके बाद उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि आप सब देखिए सुरक्षाबलों ने छात्रों को कितनी बुरी तरह से पीटा। उन्होंने आगे कहा कि आखिर देश के छात्रों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने पूछा कि छात्रों ने ऐसा क्या गलत किया है कि उनके सामने सुरक्षा बल हथियार ताने खड़े हैं। राहुल गांधी ने कहा कि छात्र शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और सिर्फ अपनी मांगें उठा रहे हैं। उनका कहना है कि छात्र केवल इतना चाहते हैं कि उन्हें एक निष्पक्ष और न्यायसंगत शिक्षा व्यवस्था मिले, जो उनका अधिकार है। राहुल गांधी ने कहा कि देश के कई छात्र अत्यधिक मानसिक दबाव का सामना कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा से ठीक पहले पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आती हैं, जिससे छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में कई छात्रों ने आत्महत्या तक कर ली है। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों की आवाज सुनी जानी चाहिए और उन्हें एक भरोसेमंद तथा निष्पक्ष शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

'क्या देश आपके अहंकार से चलेगा'

पीएम आवास तक मार्च को लेकर बीजेपी का राहुल गांधी से तीखा सवाल

नई दिल्ली। नीट विवाद से शुरू हुई विरोध की चिंगारी अब देश की सियासत में जबरदस्त गर्माहट पैदा कर चुकी है। ऐसे में कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की तरफ से मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास की तरफ किए गए विरोध मार्च के अगले दिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उन पर तीखा हमला बोला है। भाजपा ने राहुल गांधी के इस कदम को गैर-जिम्मेदाराना और शर्मनाक बताते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा का अनादर किया है। इसके जवाब में भाजपा ने देश भर में कांग्रेस दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करने का एलान किया है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी से सवाल किया कि क्या यह देश आपकी जिद और अहंकार से चलेगा? अपने बयान में रवि शंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के पारिवारिक इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी ऐसे परिवार से आते हैं जिसके तीन सदस्य, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उन्हें प्रधानमंत्री आवास की गरिमा और सुरक्षा का अहसास होना चाहिए था। रवि शंकर प्रशाद ने कहा कि इसके बावजूद, पीएम आवास के गेट पर धरना देना बेहद गैर-जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा कि सरकार NEET परीक्षा के मुद्दे पर संसद में बहस के लिए तैयार थी, लेकिन राहुल गांधी बातचीत छोड़कर सड़क पर उतर आए।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का विपक्ष पर हमला: बोले- छात्रों को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के दौरान युवाओं और छात्रों के मुद्दे पर जारी सियासी घमासान के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग देश के छात्रों और युवाओं का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हथियार के रूप में कर रहे हैं। उन्होंने इसे छात्रों को भटकाने का एक असफल प्रयास करार दिया। राजनाथ सिंह ने विश्वास जताया कि भारत का समझदार युवा इन सभी कोशिशों को अच्छी तरह समझता है और वह विकास तथा राष्ट्र निर्माण का रास्ता ही चुनेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार छात्रों और युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने तथा उनके कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

खड़गे की शर्त: पहले इस्तीफा फिर NEET पर चर्चा; नड्डा बोले- विपक्ष गैर-जिम्मेदार

संसद में लगातार बवाल जारी है। राज्यसभा में, केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाया है। नड्डा ने राज्यसभा में कहा कि INDI गठबंधन का व्यवहार बहुत गैर-जिम्मेदाराना है। हम संसद में उनके इस लोकतंत्र-विरोधी व्यवहार को साफ देख सकते हैं। संसदीय मर्यादा को तार-तार किया जा रहा है और लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन हो रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अभी-अभी बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नड्डा ने साफ तौर पर कहा कि हमारी सरकार NEET पेपर लीक और उससे जुड़े सभी मामलों पर भी चर्चा करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार पारदर्शी है। यह एक ऐसी सरकार है जो हमेशा लोगों के हित में काम करती है। इसलिए, हम उनकी (विपक्ष की) जन-विरोधी गतिविधियों की कड़ी निंदा करते हैं। वे लोकतंत्र या लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं करते हैं। राज्यसभा में NEET UG 2026 पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर निष्पक्ष चर्चा होनी है, तो शिक्षा मंत्री को पहले इस्तीफ़ा देना चाहिए। जब तक वे इस्तीफ़ा नहीं देते, तब तक यहां निष्पक्ष चर्चा नहीं हो पाएगी। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मैं सदन में सरकार का पक्ष रखना चाहता हूँ। मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही सरकार कह रही है कि हम सभी अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। हम शुरू से ही NEET परीक्षा के पेपर लीक पर चर्चा के लिए तैयार हैं। हम अभी भी तैयार हैं। हमने कांग्रेस नेताओं और दूसरी पार्टियों के नेताओं से भी कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है।

लोकसभा में दिखा अखिलेश का गुस्सा, बोले- समझौता कर लिया क्या

अखिलेश ने कहा कि पेपर लीक का मुद्दा कांग्रेस, सपा का नहीं है। युवाओं और छात्रों का है। अखिलेश ने स्पीकर को संबोधित करते हुए कहा कि आपने बीजेपी को बोलवा दिया, कांग्रेस को बोलवा दिया। समझौता कर लिया आपने क्या। आपने हमें क्यों नहीं बोलने दिया। ये ठीक नहीं है। छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो वे सड़कों पर आएंगे। छात्रों का हाथ तोड़ा गया। क्या आप बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे। हम लोग मजबूरी में पीएम आवास पर गए। अगर आप हमारी बात सुन लेते तो हम नहीं जाते।

छात्रों पर लाठीचार्ज मामले में दिल्ली हाई सख्त.. केंद्र और पुलिस को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली, एजेंसी। जंतर-मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से इस मामले में 4 सप्ताह हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस को वीडियो और CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।

ASG SV राजू ने कहा कि अगर कोई संज्ञेय अपराध बनता है और पुलिस को इसकी जानकारी मिलती है, तो वे कार्रवाई करेंगे। कोर्ट ने अनीता ठाकुर मामले में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का जिक्र किया जिसमें कहा गया है कि ऐसी गलतियों के लिए पब्लिक लॉ के तहत भी उपाय मांगे जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि मामले की मेरिट पर कोई राय जाहिर किए बिना, वह बस उनसे अपना जवाब दाखिल करने और अपनी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के अनुसार रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए कह रहा है।

आदेश देते हुए कोर्ट ने चार हफ़्ते के भीतर (दिल्ली पुलिस और भारत सरकार की ओर से) एक काउंटर-एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस बीच, कोर्ट निर्देश दिया कि रिट याचिकाओं में बताई गई घटना से संबंधित सभी जरूरी रिकॉर्ड – जैसे CCTV फुटेज और कोई भी वीडियोग्राफी को दिल्ली पुलिस या भारत सरकार द्वारा जारी SOP के अनुसार सुरक्षित रखा जाए।

देश के कई राज्यों में बाढ़-बारिश से भयंकर तबाही, 50 से ज्यादा मौतें

नई दिल्ली, एजेंसी। देश के कई राज्यों में इस वक्त मानसूनी बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचा रखी है। असम से लेकर हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर तक कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं से जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। नदियां उफान पर हैं, घर मलबे में तब्दील हो गए हैं और अब तक दर्जनों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रशासन और रेस्क्यू टीमें लगातार राहत-बचाव के काम में जुटी हुई हैं, लेकिन हालात अब भी बेहद चिंताजनक बने हुए हैं।

असम में बाढ़ से हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (रस्ष्ठरूर) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में 21 लोगों की जान चली गई, जिससे मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 31 तक पहुंच गया है। राज्य के 16 जिलों में 5.64 लाख से अधिक लोग इस भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं। सबसे बुरा हाल शिवसागर जिले का है, जहां अकेले 3.59 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। चराइदेव, जोरहाट और गोलाघाट में भी स्थिति गंभीर है। ब्रह्मपुत्र, दिखो, देसांग और धनसिरी समेत कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसके चलते रेलवे ट्रैक डूब गए हैं और कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा खुद प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति की समीक्षा करेंगे।

हिमाचल में फटा बादल, कई मकान मलबे में दबे

पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश आफत बनकर बरसी है। कांगड़ा जिले की बोह घाटी में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के चलते कई मकान, गौशालाएं और खेत मलबे में दब गए। गनीमत यह रही कि समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकाल लिया गया, जिससे कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, हालांकि कई मवेशियों की जान चली गई। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए रेड अलर्ट के बाद कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में सभी स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। किन्नौर में भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग-5 समेत प्रदेश की 36 सड़कें और कई पेयजल योजनाएं ठप पड़ गई हैं।

अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की, बोले- देश को आपकी जरूरत

नई दिल्ली, एजेंसी। जंतर-मंतर पर चल रहे आंदोलन के बीच सीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत दीपके ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से अपना अनशन समाप्त करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक का जीवन देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और उनकी सेहत को देखते हुए अब उन्हें भूख हड़ताल खत्म कर देनी चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अनशन खत्म होने का मतलब आंदोलन का खत्म होना नहीं होगा। दीपके ने कहा कि जब तक उनकी मुख्य मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रहेगा।

अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि सोनम वांगचुक के अनशन का 25वां दिन है और बिना भोजन के इतने लंबे समय तक रहने से उनके जीवन पर गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा, ₹देश को उनकी जरूरत है। मैं उनसे अनशन खत्म करने की अपील करता हूं। लेकिन हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं।₹ उन्होंने कहा कि यदि सोनम वांगचुक अनशन समाप्त भी कर देते हैं, तब भी प्रदर्शन जारी रहेगा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से पीछे नहीं हटेंगे।

अभिजीत दीपके ने आंदोलन को लेकर क्या भरोसा दिया?

दीपके ने कहा कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा और किसी भी ऐसी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी जिससे आंदोलन या देश की छवि को नुकसान पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन महात्मा गांधी और डॉ. भीमराव आंबेडकर के बताए अहिंसक रास्ते पर चलेगा। उन्होंने समर्थकों से भी अपील की कि वे संयम बनाए रखें और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रखें। उनके अनुसार आंदोलन का उद्देश्य केवल जवाबदेही तय कराना है।

दिल्ली हाईकोर्ट में किस मामले पर सुनवाई होगी?

बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई होनी है, जिसमें जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक के अनशन के दौरान पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है। याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ करेगी।

याचिका में पुलिस कार्रवाई को लेकर क्या आरोप लगाए गए?

याचिका में दावा किया गया है कि सोनम वांगचुक और अन्य प्रदर्शनकारियों ने 28 जून 2026 से शिक्षा व्यवस्था और कथित परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी। इसमें कहा गया है कि 17 जुलाई तक प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। याचिका के अनुसार 18 जुलाई को पुलिस ने प्रदर्शन स्थल खाली कराया, कई प्रदर्शनकारियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध हटाया या हिरासत में लिया और बल प्रयोग किया।

ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी खबर, रेलवे खत्म कर रहा 300 स्टॉपेज ; अब 45 मिनट पहले पहुंचेंगी प्रीमियम ट्रेनें

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय रेलवे लंबी दूरी और प्रीमियम ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इसके तहत देशभर में प्रायोगिक आधार पर दिए गए 300 से अधिक स्टॉपेज को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का खाका तैयार कर लिया गया है। रेलवे की यह नई व्यवस्था अक्टूबर 2026 तक पूरी तरह लागू हो जाएगी, जिससे यात्रियों के सफर का 15 से 45 मिनट तक का बहुमूल्य समय बचेगा। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, साल 2021 से 2025 के बीच स्थानीय सांसदों, विधायकों और क्षेत्रीय जनता की मांग पर सैकड़ों स्टेशनों पर छह महीने के प्रायोगिक आधार पर ट्रेनों के ठहराव मंजूर किए गए थे। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे कस्बों के यात्रियों को सीधी रेल कनेक्टिविटी का लाभ देना था। नियम के मुताबिक मियाद पूरी होने के बाद इन स्टॉपेज की व्यावसायिक उपयोगिता की समीक्षा की गई। रेलवे बोर्ड के इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम (आईसीएमएस) के आंकड़ों में यह बात सामने आई कि ये स्टॉपेज 'न्यूनतम 15 टिकट प्रति ट्रेन प्रतिदिन' के पैमाने पर पूरी तरह फेल साबित हुए। कम यात्रियों के बावजूद ट्रेनों को रोकने से न केवल करोड़ों रुपये का ईंधन बर्बाद हो रहा था, बल्कि मुख्य मार्गों पर ट्रेनों की समयपालन व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन (आरडीएसओ) की रिपोर्ट के अनुसार, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही किसी प्रीमियम ट्रेन को एक स्टेशन पर रोकने और दोबारा उसी गति में लाने में 5 से 7 मिनट का समय बर्बाद होता है।

रोडवेज बस की ब्रेक हुई फेल... रोकने के लिए हाथ में ईंट लेकर दौड़े दरोगा-सिपाही

आर्यावर्त संवाददाता

हमीरपुर। हमीरपुर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के राठ कस्बे में मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब उरई डिपो की एक रोडवेज बस के अचानक ब्रेक फेल हो गए। भीड़भाड़ वाले बस स्टैंड रोड पर अनियंत्रित होकर दौड़ रही बस को देखकर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बिना एक पल गंवाए मोर्चा संभाल लिया। सबसे खास बात यह रही कि दरोगा समेत तीन पुलिसकर्मी हाथों में ईंट लेकर बस के आगे-आगे दौड़ पड़े और चालक को बस की रफ्तार नियंत्रित करने में मदद करते हुए बड़ा हादसा टाल दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, उरई डिपो की रोडवेज बस (UP93 BT 1687) जैसे ही राठ बस स्टैंड क्षेत्र में पहुंची, उसके ब्रेक अचानक जवाब दे गए। चालक ने बस को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन भीड़भाड़ वाले इलाके में बस लगातार आगे बढ़ती रही। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर मौजूद दरोगा और सिपाहियों ने हाथों में ईंट लेकर बस के दोनों ओर दौड़ना शुरू कर दिया। साथ ही बस के आगे-आगे चलकर ट्रैफिक हटाया, ताकि कोई राहगीर या वाहन उसकी चपेट में न आ जाए। काफी मशक्कत के बाद बस की गति कम हुई और उसे सुरक्षित रोक लिया गया।

वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

इस पूरी घटना का वीडियो वहां मौजूद किसी स्थानीय व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिसकर्मी अपनी जान की परवाह किए बिना अनियंत्रित बस के साथ दौड़ते और रास्ता साफ कराते नजर आ रहे हैं।

स्थानीय लोगों ने बताया कैसे टला हादसा?

स्थानीय निवासी धनंजय के मुताबिक, बस उरई डिपो की थी और ब्रेक फेल होने के बाद स्थिति बेहद गंभीर हो गई थी। यदि पुलिसकर्मी तत्काल सक्रिय होकर हाथ में ईंट लेकर बस के आगे-आगे न दौड़ते और ट्रैफिक साफ न कराते, तो भीड़भाड़ वाले बस स्टैंड क्षेत्र में बड़ा हादसा हो सकता था।

फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस घटना को लेकर परिवहन विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन लोगों का कहना है कि पुलिसकर्मियों की सूझबूझ और साहस ने दर्जनों यात्रियों की जान बचा ली।

हाउस अरेस्ट के बावजूद सपाइयों ने तोड़ा पुलिस घेरा, जोरदार प्रदर्शन

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ हुई कथित धक्का-मुक्की और हिरासत के विरोध में बुधवार को जिले में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रशासन द्वारा धारा 163 बीएनएस लागू होने और कई प्रमुख नेताओं को हाउस अरेस्ट किए जाने के बावजूद सैकड़ों सपाई पुलिस का घेरा तोड़कर कलेक्ट्रेट पहुंच गए और सरकार विरोधी नारेबाजी की।

प्रदर्शन से पहले पुलिस ने सपा जिलाध्यक्ष रघुवीर यादव को उनके विवेक नगर स्थित आवास, पूर्व विधायक अरुण वर्मा को तिंदौली स्थित आवास तथा सपा प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक अनूप संडा समेत कई

नेताओं को एहतियातन हाउस अरेस्ट कर दिया। कई नेताओं के आवासों पर सुबह से ही पुलिस बल तैनात रहा। इसके बावजूद कार्यकर्ताओं का जत्था कलेक्ट्रेट पहुंच गया, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई।

मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष मोहम्मद शहजाद के नेतृत्व में सपा नेताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को पांच सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर चल रही बुलडोजर एवं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोकने, दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के साथ हुई कथित पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच कराने तथा लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई। साथ ही पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में भी आवाज उठाई गई।

इधर, समाजसेवी एवं सपा नेता विपिन प्रकाश सिंह 'दीपक' ने भी सपा नेताओं को हाउस अरेस्ट किए जाने की निंदा करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन लोकतंत्र का मूल अधिकार है और नेताओं को नजरबंद करना लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है।

आयुष्मान या आय-शोषण योजना, प्रसूताओं के दर्द पर बेल्ट घोटाले का खेल!

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। गरीबों को मुफ्त इलाज का सपना दिखाने वाली आयुष्मान भारत योजना जिला महिला अस्पतालों में दम तोड़ती नजर आ रही है। सरकार मंचों से स्वास्थ्य सेवाओं की सफलता के गीत गा रही है लेकिन हकीकत यह है कि ऑपरेशन के बाद दर्द से कराहती प्रसूताओं को उनके हक की एक साधारण मैटरनिटी बेल्ट तक समय पर नसीब नहीं हो रही।

आयुष्मान योजना के पैकेज में मैटरनिटी बेल्ट का स्पष्ट प्रावधान और बजट होने के बावजूद अस्पतालों में स्टॉक खत्म है बाद में आना, या फाइल चल रही है जैसे बहाने सुनने को मिलते हैं। सवाल यह है कि जब बजट आ चुका है तो बेल्ट आखिर गायब कहां हो रही है। क्या गरीब महिलाओं के हिस्से का सामान कागजों में बांटकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जा रहा है। विडंबना देखिए जिस बेल्ट की सबसे अधिक जरूरत ऑपरेशन के तुरंत बाद होती है वही मरीज को तब मिलती है जब वह या तो बाजार से खरीद चुकी होती है या दर्द झेलते-झेलते अस्पताल के कई चक्कर लगा चुकी होती है। यानी सरकारी व्यवस्था पहले मरीज को दर्द देती है फिर उसे राहत के लिए अपनी जेब ढीली करने पर मजबूर करती है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी दावे करते हैं कि आयुष्मान योजना गरीबों के लिए वरदान है लेकिन जिला अस्पतालों की तस्वीर इन दावों पर करारा तमाचा है। यदि योजना का लाभ समय पर नहीं मिल रहा तो फिर करोड़ों रुपये के बजट का हिसाब कौन देगा? जब इस मामले पर जिला महिला अस्पताल के सीएमएस रामकुमार यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जिम्मेदारी लेने के बजाय जवाब डॉक्टरों पर छोड़ दिया।

मंत्री ओम प्रकाश राजभर बोले- छात्रों की मांग जायज, राहुल-अखिलेश का आंदोलन राजनीति

आर्यावर्त संवाददाता

अंबेडकरनगर। यूपी सरकार के पंचायतीराज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने दिल्ली में नीट अभ्यर्थियों की व्यवस्थाओं में सुधार की मांग को जायज बताया लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव के आंदोलन को राजनीतिक करार देते हुए उन पर तीखा हमला बोला।

मीडिया से बातचीत में राजभर ने कहा कि छात्रों की मांग उचित है और पेपर लीक नहीं होना चाहिए, लेकिन विपक्ष छात्रों के मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि छात्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने गए थे लेकिन प्रदर्शन के दौरान देशविरोधी नारे लगाए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी, आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता छात्रों को उकसाने पहुंचे जबकि लाठीचार्ज के समय उन्हें छोड़कर चले गए।ओमप्रकाश राजभर

ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के शासनकाल में खुलेआम नकल और पेपर लीक होते थे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाया गया है। उन्होंने दावा किया कि अब नकलविहीन परीक्षाएं हो रही हैं और पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।

मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर से खुरपका-मुंहपका (एफएमडी) टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने टीकाकरण टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा पौधरोपण और जल संरक्षण का संदेश भी दिया।

उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज का वह समर्थन नहीं करते लेकिन जो लोग छात्रों को भड़काते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार में नौकरियों के लिए बोली लगती थी, जबकि वर्तमान सरकार ने बिना भ्रष्टाचार के प्रदेश में नौ लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं।

प्रभारी मंत्री ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा में सुधार हुआ है, जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से राजधानी तक पहुंच आसान हुई है तथा अधिकांश घरों में शौचालय बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार विकास और सुशासन के एजेंडे पर लगातार काम कर रही है।

राजकीय पशु चिकित्सालय के मुख्यद्वार पर बना कूड़ाघर, संक्रामक बीमारियों का बढ़ा खतरा

आर्यावर्त संवाददाता

बल्दीराय/सुल्तानपुर। विकासखण्ड धनपतगंज स्थित राजकीय पशु चिकित्सालय का मुख्यद्वार इन दिनों कूड़ाघर में तब्दील हो गया है। चिकित्सालय परिसर के बाहर लंबे समय से भारी मात्रा में डंप कूड़ा और गंदगी जमा होने से बरसात के मौसम में सड़ांध फैल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे मच्छर, मक्खी तथा अन्य रोग फैलाने वाले कीट तेजी से पनप रहे हैं, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। शासन की स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ ग्राम और जनस्वास्थ्य सुरक्षा की मंशा के विपरीत जिम्मेदार विभाग इस गंभीर समस्या से आंखें मूंदे हुए हैं। कूड़े से संक्रमण का खतरा, पशु और इंसान दोनों प्रभावित होने की आशंका चिकित्सकों के अनुसार खुले में सड़ता कूड़ा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टायफाइड, दस्त, हैजा तथा त्वचा संबंधी संक्रमण जैसी बीमारियों को बढ़ावा देता है। यही नहीं, पशु चिकित्सालय में आने वाले पशुओं में भी संक्रमण फैलने की आशंका बनी रहती है। चिंताजनक बात यह है कि पशु चिकित्सालय के ठीक बगल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा निकट ही विकासखण्ड मुख्यालय स्थित है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज, पशुपालक और कर्मचारी आते-जाते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आसपास के कुछ लोग नियमित रूप से चिकित्सालय परिसर के बाहर कूड़ा फेंकते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत और विकास विभाग की ओर से न तो कूड़ा हटवाया जा रहा है और न ही रोकथाम के कोई प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इससे शासन के स्वच्छता संबंधी निर्देशों और जनस्वास्थ्य सुरक्षा के दावों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

गंगा एक्सप्रेसवे का 60 मीटर टुकड़ा धंसा, दो दिन की बारिश ने खोल दी पोल, प्रशासन भी हुआ खामोश

आर्यावर्त संवाददाता

हरदोई। प्रयागराज को मेरठ से जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे माइलस्टोन संख्या 354 सहादतपुरवा के पास लगभग 60 मीटर का टुकड़ा सोमवार रात किसी समय धंस गया। इसकी जानकारी मिलते ही कार्यदायी संस्था के तकनीकी कर्मचारियों ने मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया। नीचे से गिट्टी भर दी और इस का डामरीकरण होना बाकी है। खास बात यह है कि यह टुकड़ा उस स्थान से सात किलोमीटर दूर है जहां से प्रधानमंत्री ने इसका लोकार्पण किया था। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण 36,230 करोड़ रुपये से हुआ है।

बीते 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का लोकार्पण मल्लावां के पास एक जनसभा में किया था। पिछले दो दिन में हुई बारिश के कारण एक्सप्रेसवे मल्लावां के माइलस्टोन संख्या 354 पर धंस गया। हालांकि इस कारण यातायात बाधित नहीं हुआ।

टुकड़ा धंसने की जानकारी पर मंगलवार सुबह से ही यहां मरम्मत का काम शुरू हो गया। जहां पर एक्सप्रेसवे धंसा था वहां नीचे से गिट्टी ऊपर तक भरने का काम भी शाम चार बजे तक पूरा कर लिया गया। पूरे मामले पर जिला प्रशासन ने कोई टिप्पणी नहीं की।

कार्यदायी संस्था के तकनीकी यूनिट हेड प्रतिनिधि राजेश मिश्रा ने बताया कि लखनऊ से मौके के लिए रवाना हो गए हैं। आशंका जताई कि 48 घंटे की बारिश के कारण कहीं कोई समस्या आई होगी। मरम्मत का काम तो रुटीन में चलता ही रहता है।

हुसैनिया मेड़ई खां अमहट में जुलूस का आयोजन किया गया

सुल्तानपुर। मंगलवार को बब्बर अब्बास खान व मोहम्मद मुत्तकी खान की अगुवाई में हुसैनिया मेड़ई खां अमहट में रात 8बजे एक मजलिस का आयोजन किया गया जिसमें सबसे पहले पेश ख्वानी आबिस रजा सुल्तानी व सज्जाद सुल्तानपुरी ने की और मजलिस मौलाना तौसीफ हुसैन खां ने पढ़ी। उन्होंने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बताया है कि आज का इन्सान अच्छा लेबास पहेन कर बाजार में अकड़ कर चलता है लेकिन उसको यह नहीं मालूम की उसका कफ़न भी इसी बाजार में मौजूद है और इसके बाद उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जवान बेटे अली असगर का मसायब पढ़ा संचालन फाखिर रजा सुल्तानपुरी ने की और अंजुमन असगरिया गोराबारिक अंजुमन असगरिया कदीम गोराबारिक अमहट अंजुमन पंजतनी तुराबखानी अंजुमन जीनतुल अजा कदीम अलीगढ़ अंजुमन जीनतुल अजा रजिस्टरड अलीगढ़ अंजुमन जीनतुल अलीगढ़ अंजुमन गुलजारे हुसैनी अलीनगर अंजुमन कमर बनी हाशिम अमहट अंजुमन गुन्चये कर्बला अमहट नौहा मातम किया।

ऐसी लट्ठबाजी देखी नहीं होगी... सड़क निर्माण के विवाद में गांव बना रणभूमि, जमकर चले डंडे-ईंट-

आर्यावर्त संवाददाता

बागपत। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में सड़क निर्माण को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। बड़ौत शहर कोतवाली क्षेत्र के बाजिदपुर गांव में दो पक्ष आमने-सामने आ गए और जमकर लाठी-डंडे, ईंट और पत्थर चले। इस खूनी संघर्ष में एक ही परिवार के पांच लोग घायल हो गए। घटना का वीडियो किसी ग्रामीण ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में यह मामला चर्चा का विषय बन गया।

जानकारी के अनुसार, बाजिदपुर गांव में सड़क निर्माण को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई थी। विवाद धीरे-धीरे इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से लोग बड़ी संख्या में मौके पर जुट गए। देखते ही देखते गाली-गलौज मारपीट में बदल गई और दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लाठी-

डंडों से हमला शुरू कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि महिलाओं ने भी मोर्चा संभाल लिया और दोनों तरफ से ईंट-पत्थर चलने लगे।

जमकर चली लाठियां

वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि गांव की गली कुछ ही मिनटों में रणभूमि में तब्दील हो गई। लोग एक-दूसरे पर लाठियां बरसा रहे हैं, जबकि आसपास अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने किसी तरह बीच-बचाव कर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की।

मारपीट में घायल हुए एक ही परिवार के पांच लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही बड़ौत शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया। इसके बाद पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 11 नामजद आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पुलिस मामले की जांच में जुटी

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। वीडियो की सत्यता की पुष्टि की जा रही है और उसमें दिखाई दे रहे लोगों की पहचान कर उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव में पुलिस बल तैनात कर स्थिति पर नजर रखी जा रही है, ताकि किसी प्रकार का नया विवाद उत्पन्न न हो। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। सड़क निर्माण को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

लखीमपुर खीरी में शारदा का रौद्र रूप, बाढ़ के पानी में डूबीं सड़कें, 12 से अधिक गांवों का संपर्क कटा

आर्यावर्त संवाददाता

लखीमपुर खीरी। बनबसा बैराज से एक लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के बाद उफनाई शारदा नदी ने लखीमपुर खीरी के पलियाकलां में खतरे का निशान लांघकर गांवों की राह निगल ली है। निर्धारित 154.590 मीटर के खतरे के निशान को पार कर मंगलवार शाम चार बजे नदी का जलस्तर 154.690 मीटर तक पहुंच गया। बाढ़ का पानी सड़कों और खेतों तक पहुंच गया। मझौरा से इमलिया जाने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरह बंद होने से एक दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क कट गया।

पलिया के मेलाघाट पर कब्रिस्तान के पास और कर्बला के निकट खैराना मार्ग के रपटा पुल पर पानी तेज बहने लगा। मझौरा-इमलिया मुख्य मार्ग बंद होने से इमलिया फॉर्म, जंगल नंबर सात,

छंगा टांडा, जमुनहा, सूरजपुर, देशराज टांडा, ढकिया, बजेड़ा, कुंवरपुर, रेती पुरवा, सापुतारा, जसकरण सिंह, गिंधी पाल और मंदिर सिंह आदि गांवों के लोगों का संपर्क कट गया है। अब उन्हें भीरा होकर लंबा चक्कर लगाकर पलिया पहुंचना पड़ रहा है।

रेलवे लाइन के किनारे भरा पानी

बोझवा ग्राम पंचायत के मटहिया में बाढ़ का पानी रेलवे लाइन के किनारे तक पहुंच गया है, जबकि बरुआ कला, छोटा बरुआ और दौलतापुर में फसलें डूब गईं। दौलतापुर में मगरमच्छों के आतंक ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। शारदा के उफान और फैले पानी के साथ मगरमच्छ गांव के अंदर और सड़कों तक पहुंच रहे हैं। बीती शाम एक मगरमच्छ ट्रैक्टर के सामने से गुजरता दिखा, जबकि दूसरा आराम करता नजर आया। ग्रामीणों के मुताबिक, मगरमच्छ अब तक तीन-चार कुत्तों को अपना निवाला बना चुके हैं। ग्राम प्रशासक प्रतिनिधि शकील अहमद ने वन क्षेत्राधिकारी रमाकांत सक्सेना को जानकारी दी, जिसके बाद एक टीम मगरमच्छों को पकड़ने पहुंची। टीम ने लोगों को जागरूक भी किया।

डीएम व एडीएम ने कटान प्रभावितों से की मुलाकात

निघासन में डीएम अंजनी कुमार ने मंगलवार को कटान प्रभावित परिवारों की समस्याएं सुनीं। अधिकारियों को राहत एवं पुनर्वास से जुड़े सभी कार्य संवेदनशीलता और प्राथमिकता के आधार पर कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और शासन की ओर से हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने निघासन एसडीएम यदुवीर सिंह के साथ प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाई। बुधवार को खाद्यान्न किट का वितरण कराया जाएगा, ताकि किसी परिवार को आवश्यक वस्तुओं के लिए परेशानी न हो।

ग्रंट नंबर-12 के करीब 200 परिवारों के 500 लोगों ने स्थायी पुनर्वास न होने पर 19 जुलाई को चुनाव में मतदान बहिष्कार का एलान किया था। इस मुद्दे पर संवाद न्यूज एजेंसी की खबर अमर उजाला में प्रमुखता से प्रकाशित हुई थी। खबर के बाद मंगलवार को अधिकारी पहुंचे और राहत एवं पुनर्वास की तैयारियों की समीक्षा की।

बझेड़ा तटबंध पर कटान रोकने का काम शुरू

बिजुआ में बझेड़ा तटबंध पर कटान शुरू होने और खबर प्रकाशित होने के अगले दिन बाढ़ खंड की टीम मौके पर पहुंची और कटान रोकने का काम शुरू कराया। कटान वाले स्थान पर मिट्टी के बोरे डालकर बचाव कार्य किया गया और लगातार निगरानी की बात कही गई। ब्लॉक के बिजुआ बझेड़ा, करसौर, कोरियाना, रूरासुल्तानपुर, तनसुखपुरवा, बेलहासिकटिहा, दंबल-टांडा, रामनगर-कला, रेउतीपुरवा, गुजारा, असाढ़ी और रामेश्वरापुर सहित गांव शारदा के किनारे हैं। इनमें बझेड़ा और गुजारा में हल्का कटान शुरू हो गया था। संभावित बाढ़ से निपटने के लिए राजस्व, सिंचाई, पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें गांवों में तैनात हैं। चार बाढ़ राहत केंद्र और तीन बाढ़ चौकियां सक्रिय कर दी गई हैं। तहसील प्रशासन ने अधिकारियों को 24 घंटे सतर्क रहने और आपात स्थिति में तत्काल राहत-बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

बाढ़ खंड के अधिशासी अभियंता अजय कुमार ने बताया कि गांव बझेड़ा में तटबंध के छोर पर मामूली कटान शुरू हुआ था, जिसका मरम्मत कार्य पूरा करा दिया गया है। अब कोई खतरा नहीं है। लगातार निगरानी की जा रही है।

डेढ़ करोड़ की कटानरोधी परियोजना का 30 मीटर हिस्सा घाघरा में समाया

धौरहरा इलाके में भदईपुरवा गांव के पास करीब डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से चार वर्ष पूर्व बनी कटानरोधी परियोजना का लगभग 30 मीटर हिस्सा घाघरा नदी में समा गया। इससे भदईपुरवा गांव और आसपास की कृषि भूमि पर कटान का खतरा बढ़ गया है। तेज बहाव के कारण बचाव कार्य में दिक्कत आ रही है। अब वायर क्रेट (लोहे के जाल) में ईंट के रोड़े भरकर नदी किनारे डालकर कटान रोकने का प्रयास किया जाएगा। ग्रामीणों के अनुसार, सरैया से मिर्जापुर गांव तक घाघरा नदी के कटान से सुरक्षा के लिए चार वर्ष पूर्व परियोजना का निर्माण कराया गया था, लेकिन नदी के लगातार तेज होते बहाव से इसका एक हिस्सा कटकर नदी में बह गया।

'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के अंतर्गत लायंस क्लब मिड टाउन का वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न

सुल्तानपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रेरणा से संचालित ₹एक पेड़ माँ के नाम₹ अभियान के अंतर्गत लायंस क्लब सुल्तानपुर मिड टाउन द्वारा अटल पर्यावरण पार्क, सुल्तानपुर में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम उत्साहपूर्वक सम्पन्न हुआ।

कार्यक्रम में क्लब के अध्यक्ष लायन प्रमोद पुरी, सचिव डॉ. राजेंद्र कपूर, लायन डॉ. डी.एस. मिश्रा, डॉ. आत्मजीत सिंह, लायंस क्लब के चार्टर प्रेसिडेंट सरदार बलदेव सिंह, डॉ. बी.पी. सिंह, डॉ. एस.के. गोयल, लायन पी.के. सिंह, डॉ. संजय खत्री, राकेश पालीवाल, लायन भारती पुरी, लायन मधु कपूर, लायन अंजली श्रीवास्तव, लायन स्वाती खत्री, अखिलेश पांडे सहित अनेक गणमान्य सदस्य एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

गोरखपुर में बूथ अध्यक्षों को सीएम योगी का चुनावी मंत्र, सपा-कांग्रेस पर बोला हमला, बोले- 'जो बूथ जीतेगा, वही चुनाव जीतेगा'

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्षों को संगठन मजबूत करने और बूथ स्तर पर सक्रिय रहने का मंत्र दिया। गोरखपुर में आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि दोनों दल झूठे नैरेटिव और भ्रम फैलाने की राजनीति करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी सत्य, विकास और जनकल्याण की राजनीति करती है।योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित गोरखपुर शहर और गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों के 892 बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी बूथ अध्यक्ष विपक्ष की ₹शरारती साजिशों₹ और नकारात्मक प्रचार से सतर्क रहें तथा जनता के बीच सरकार की उपलब्धियों को लेकर लगातार संवाद बनाए रखें।मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में नौकरी हो या सरकारी योजनाओं का लाभ, हर जगह 'सैफई सिंडिकेट' का प्रभाव दिखाई देता था। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय एक विशेष वर्ग और समूह का वर्चस्व था, जबकि वर्तमान सरकार ने पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की है।उन्होंने कहा कि विपक्ष का सिद्धांत एक झूठ को बार-बार बोलकर उसे सच साबित करने का है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सत्य और विश्वास की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि समाज में सत्य और असत्य, देव और दानव जैसी दो प्रवृत्तियां हमेशा रहती हैं और भाजपा हमेशा सत्य, धर्म और जनकल्याण के साथ खड़ी रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने डॉ. भीमराव आंबेडकर, महर्षि वाल्मीकि, संत रविदास और सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे महापुरुषों को उचित सम्मान नहीं दिया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ने इन महापुरुषों के सम्मान में अनेक कार्य किए, जबकि विपक्ष ने जिन्ना का महिमामंडन किया।उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने आरक्षण और आर्थिक सहायता जैसे मुद्दों पर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले किसानों को भड़काने की कोशिश की गई और अब छात्रों को आंदोलन के नाम पर भड़काया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ता इन प्रयासों को बेनकाब करें और जनता के बीच सही जानकारी पहुंचाएं।मुख्यमंत्री ने बूथ अध्यक्षों को संगठन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए कहा कि चुनाव की वास्तविक लड़ाई बूथ पर लड़ी जाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मेरा बूथ सबसे मजबूत' मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि 'जो बूथ जीतेगा, वही चुनाव भी जीतेगा।' उन्होंने कहा कि बूथ किसी भी चुनाव का वास्तविक कुरुक्षेत्र होता है और बूथ पर मजबूत जनसंपर्क ही जीत सुनिश्चित करता है।उन्होंने बूथ अध्यक्षों की तुलना सीमा पर तैनात सैनिकों से करते हुए कहा कि जिस प्रकार सैनिक देश की सुरक्षा करते हैं, उसी प्रकार बूथ अध्यक्ष संगठन की मजबूती और चुनावी सफलता की नींव होते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि बूथ कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी।मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि आज देश के 80 करोड़ और उत्तर प्रदेश के 16 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है। आवास, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के पात्र लोगों तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण व्यवस्था से सरकारी योजनाओं में पूरी पारदर्शिता आई है।उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ नौ लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं, जिनमें किसी प्रकार की सिफारिश, भ्रष्टाचार या धनबल का प्रभाव नहीं रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों में भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता का अभाव था।मुख्यमंत्री ने गोरखपुर सहित प्रदेश में हुए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में प्रभु श्रीराम का भव्य मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, विंध्याचल धाम और नैमिषारण्य के विकास जैसे कार्य भारतीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण के उदाहरण हैं।उन्होंने गोरखपुर में बने छह लेन फ्लाईओवर को शहर के विकास की बड़ी उपलब्धि बताते हुए अगले दिन होने वाले उसके लोकार्पण समारोह में लोगों को आमंत्रित किया और कहा कि नागरिक फ्लाईओवर पर जाकर तस्वीरें लें तथा उन्हें सामाजिक माध्यमों पर साझा करें।सम्मेलन का शुभारंभ डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर तथा वंदे मातरम् के सामूहिक गायन के साथ हुआ। कार्यक्रम को सांसद रविकिशन शुक्ल, महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक विपिन सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉ. धर्मेंद्र सिंह तथा क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय ने भी संबोधित किया।

जैव ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा में अग्रणी बनने की ओर बढ़ा उत्तर प्रदेश, अगस्त में होगा अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा महाकुंभ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश को जैव ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में बुधवार को लखनऊ स्थित इन्वेस्ट यूपी सभागार में आगामी अंतरराष्ट्रीय जैव ऊर्जा एवं प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी की तैयारियों को लेकर उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने की। इसमें आयोजन की रूपरेखा, निवेश की संभावनाओं, उद्योगों की भागीदारी तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की विस्तृत समीक्षा की गई।बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा आशीष गोयल, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के निदेशक रविंद्र सिंह, सचिव पंकज सिंह, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि तथा जैव ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञ मौजूद रहे।

उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन को नई मजबूती, अडानी स्किल्स एंड एजुकेशन के साथ समझौता

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के युवाओं को देश और विदेश में बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत सेवायोजन विभाग और अडानी स्किल्स एंड एजुकेशन के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य युवाओं के कौशल अंतर को दूर कर उन्हें स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।यह समझौता 20 जुलाई को बापू भवन स्थित सचिवालय सभागार में श्रम एवं सेवायोजन तथा समन्वय मंत्री अनिल राजभर और राज्यमंत्री मनोहर लाल मन्नू कोरी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। एमओयू पर सेवायोजन विभाग की निदेशक नेहा प्रकाश और अडानी स्किल्स एंड एजुकेशन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुधान्वा किमाने ने हस्ताक्षर किए।मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को देश और विदेश की रोजगार आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना है। इसके तहत विभिन्न देशों और राज्यों में रोजगार की मांग का सर्वेक्षण, प्रतिष्ठित कंपनियों को सूचीबद्ध करना, युवाओं के कौशल अंतर की पहचान कर उसे दूर करना, विदेशी रोजगार के लिए भाषा प्रशिक्षण, प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण तथा रोजगार मिलने के बाद भी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।उन्होंने बताया कि मिशन के अंतर्गत अब तक 6,004 निर्माण श्रमिकों को इजराइल भेजा जा चुका है, जो विभाग की एक बड़ी उपलब्धि है।

साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को मिलेगा बल, राज्य परिवर्तन आयोग और लखनऊ विश्वविद्यालय के बीच हुआ समझौता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण और विकासोन्मुख अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य परिवर्तन आयोग और लखनऊ विश्वविद्यालय के बीच महत्वपूर्ण समझौता किया गया। बुधवार को योजना भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विकास एवं नीति अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत नीति एवं विकास अनुसंधान प्रकोष्ठ की स्थापना के लिए दोनों संस्थानों ने समझौता किया।समझौते पर राज्य परिवर्तन आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार सिंह (सेवानिवृत्त आईएएस) तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जे.पी. सैनी ने हस्ताक्षर किए। यह समझौता प्रारंभिक रूप से तीन वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा, जिसे आवश्यकता पड़ने पर प्रतिवर्ष बढ़ाते हुए दो वर्ष तक और जारी रखा जा सकेगा।

आशियाना में चेन स्नेचिंग का खुलासा, पुलिस ने शातिर लुटेरे को दबोचा

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। राजधानी के आशियाना क्षेत्र में महिला से चेन छीनने की घटना का पुलिस ने सफल खुलासा करते हुए एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से लूटी गई सोने की चेन का एक हिस्सा भी बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पहले भी लूट और चोरी की कई घटनाओं में जेल जा चुका है तथा उसके आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है।पुलिस के मुताबिक 14 जुलाई 2026 को शोभित सरन ने आशियाना थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 26 जून की रात करीब 9:47 बजे वह अपनी पत्नी को चिकित्सक के यहां से दिखाकर स्कूटी से घर लौट रहे थे। इसी दौरान मानसरोवर योजना स्थित पार्क संख्या-10 के पास मोटरसाइकिल सवार अज्ञात बदमाश उनकी पत्नी के गले से सोने की चेन झपटकर फरार हो गए। शिकायत के आधार पर आशियाना थाने में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई।घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीम ने आसपास लगे कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदिग्ध की पहचान की गई। इसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 21 जुलाई की रात करीब 11:30 बजे रमाबाई अंबेडकर मैदान रैली स्थल रोड से राज रावत (22 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया।पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह अपने खर्च पूरे करने के लिए रात के समय मोबाइल और सोने की चेन झपटने की वारदातों को अंजाम देता था।

• संक्षेप •

बीबीएयू में नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए छात्रावास आवेदन शुरू

लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू), लखनऊ में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए छात्रावास आवंटन की आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी पात्र विद्यार्थियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है, ताकि छात्रावास आवंटन की प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी की जा सके।विश्वविद्यालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार, छात्रावास आवेदन का आवेदन प्रपत्र का संपर्क सूत्र नवप्रवेशित विद्यार्थियों के विश्वविद्यालय में पंजीकृत ई-पत्र पते पर भेज दिया गया है। सभी पात्र विद्यार्थियों को 26 जुलाई सायं 6 बजे तक आवेदन प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी।विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि यदि किसी विद्यार्थी को आवेदन का संपर्क सूत्र अपने ई-पत्र में दिखाई नहीं देता है, तो वह अनचाहे संदेश (स्पैम) वाले फोल्डर की भी जांच अवश्य कर ले। कई बार तकनीकी कारणों से संदेश उसी फोल्डर में पहुंच जाते हैं।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा केवल बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए ही उपलब्ध कराई गई है।विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी विद्यार्थियों से अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करते हुए समय रहते आवेदन करने का आग्रह किया है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में उत्तर प्रदेश बना देश का अग्रणी राज्य

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ने लाखों ग्रामीण परिवारों के जीवन में बदलाव की नई कहानी लिखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार मिशन मोड में कार्य करते हुए यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी पात्र परिवार कच्चे, जर्जर या बेघर अवस्था में रहने को मजबूर न रहे। सरकार का लक्ष्य मार्च 2029 तक सभी पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का आवास उपलब्ध कराना है।ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के क्रियान्वयन में पूरे देश के लिए मिसाल कायम की है। प्रदेश को स्वीकृत 36.56 लाख आवासों के लक्ष्य के सापेक्ष 36.39 लाख आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। यह 99.53 प्रतिशत उपलब्धि है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर आवास पूर्णता का औसत लगभग 76.73 प्रतिशत है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश लक्ष्य प्राप्ति और समयबद्ध क्रियान्वयन दोनों में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है।योजना की सबसे बड़ी विशेषता निर्माण कार्य की गति रही है। प्रदेश में लगभग 90 प्रतिशत आवास मात्र 10 माह के भीतर पूर्ण किए गए हैं। प्रशासनिक दक्षता, प्रभावी निगरानी तथा जनप्रतिनिधियों के सहयोग से आवास निर्माण तेजी से पूरा किया गया। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास निर्माण की गति के मामले में देश में अग्रणी बनकर उभरा है।

फतेहपुर से शुरू हुआ खुरपका-मुंहपका टीकाकरण अभियान, 45 दिनों में लगभग छह लाख पशुओं को लगेगा टीका

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पशुओं को खुरपका-मुंहपका जैसी संक्रामक बीमारी से बचाने के लिए बुधवार से व्यापक टीकाकरण अभियान शुरू हो गया। पशुधन एवं दुग्ध विकास राज्य मंत्री कृष्णा पासवान ने फतेहपुर से अभियान के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान को पूरी गंभीरता, गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ संचालित करते हुए सभी पात्र पशुओं का शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए।राज्य मंत्री ने बताया कि पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत खुरपका-मुंहपका टीकाकरण अभियान का आठवां चरण 22 जुलाई से शुरू होकर 8 सितंबर, 2026 तक यानी कुल 45 दिनों तक चलेगा।उन्होंने बताया कि फतेहपुर जनपद के 13 विकास खंडों में अभियान के संचालन के लिए 46 टीमें गठित की गई हैं। प्रत्येक टीम की निगरानी उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी और पशु चिकित्साधिकारी करेंगे।

प्रदेश की कानून व्यवस्था पर पुलिस मुख्यालय की पैनी नजर, डीजीपी राजीव कृष्ण ने कंट्रोल रूम से संभाला मोर्चा

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में कानून व्यवस्था को पूरी तरह से सुदृढ़ बनाए रखने के लिए पुलिस मुख्यालय लगातार सक्रिय है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने बुधवार को पुलिस मुख्यालय के कंट्रोल रूम से प्रदेशभर की सुरक्षा व्यवस्था और मौजूदा हालात की गहन समीक्षा की। इस दौरान अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) अमिताभ यश सहित पुलिस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी कंट्रोल रूम में मौजूद रहे और प्रदेश के विभिन्न जिलों की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी।पुलिस मुख्यालय से सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क स्थापित कर स्थिति की जानकारी ली जा रही है। जिलों से मिल रहे फीडबैक के आधार पर कानून व्यवस्था का आकलन किया जा रहा है तथा आवश्यकतानुसार वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं।वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी पुलिस आयुक्तों, परिक्षेत्रीय अधिकारियों और जिला पुलिस प्रमुखों को अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने, संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने तथा किसी भी परिस्थिति से तत्काल और प्रभावी ढंग से निपटने के निर्देश दिए हैं।पुलिस मुख्यालय द्वारा सोशल मीडिया और अन्य संचार माध्यमों पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी प्रकार की भ्रामक या अफवाह फैलाने वाली गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। अधिकारियों ने सभी जिलों को निर्देशित किया है कि अफवाहों पर कड़ी नजर रखें और आमजन से संवाद बनाए रखते हुए शांति एवं सौहार्द का वातावरण कायम रखें।डीजीपी राजीव कृष्ण ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। प्रत्येक घटना पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहे।पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं तथा वरिष्ठ अधिकारी लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बल और संसाधन भी तत्काल उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि प्रदेश में पूरी तरह शांति और सामान्य जनजीवन बना रहे।

देश के 65 प्रतिशत मोबाइल फोन का निर्माण उत्तर प्रदेश में, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का सबसे बड़ा केंद्र बना प्रदेश

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का सबसे बड़ा केंद्र बनकर तेजी से उभर रहा है। वर्तमान में देश में बनने वाले लगभग 65 प्रतिशत मोबाइल फोन का निर्माण उत्तर प्रदेश में हो रहा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा को केंद्र बनाकर विकसित औद्योगिक तंत्र ने प्रदेश को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के पुर्जों के निर्माण और निर्यात में भी उत्तर प्रदेश लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।औद्योगिक विकास विभाग के अनुसार नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां मोबाइल फोन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का निर्माण कर रही हैं। इसके कारण उत्तर प्रदेश आज देश के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका है।प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के पुर्जों के निर्माण में भी अग्रणी बनकर उभरा है। देश में बनने वाले कुल इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों में लगभग 55 प्रतिशत का उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। यहां मुद्रित परिपथ, प्रदर्शन पटल, संधारित्र तथा अन्य महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों का बड़े पैमाने पर निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही घरेलू उपयोग के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में भी प्रदेश लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है।इस उपलब्धि के पीछे प्रदेश सरकार की निवेश प्रोत्साहन और उद्योग अनुकूल नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2017 तथा उसके बाद किए गए संशोधनों और इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जा विनिर्माण नीति-2025 के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश में 75 से अधिक कंपनियों ने 28 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है।

राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की बैठक सम्पन्न, चढ़ावा व्यवस्था, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति और श्रावण मेले की तैयारियों पर मंथन

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को अयोध्या में आयोजित हुई। बैठक में आगामी श्रावण मास के दौरान श्रद्धालुओं की संभावित बढ़ी हुई संख्या को देखते हुए दर्शन व्यवस्था, मंदिर प्रबंधन, चढ़ावा व्यवस्था, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति तथा अन्य प्रशासनिक विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही न्यासी मंडल में रिक्त पदों की पूर्ति और विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की गई।बैठक में चढ़ावा राशि की गणना प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट पर भी चर्चा प्रस्तावित थी, लेकिन अंतिम जांच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं होने के कारण इस विषय पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। न्यास ने इस मामले में उच्चतम न्यायालय में लंबित याचिकाओं की सुनवाई की प्रगति और न्यायालय के निर्देशों का भी संज्ञान लिया।न्यासियों ने मंदिर परिसर में लगे निगरानी कैमरों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए संतोष व्यक्त किया कि चढ़ावा गणना कक्ष सहित सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थापित कैमरों की पहुंच संबंधित सुरक्षा अधिकारियों को पहले से उपलब्ध करा दी गई है। इससे सुरक्षा और पारदर्शिता दोनों सुनिश्चित हो रही हैं।बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक संस्थान की टकसाल के साथ स्वर्ण एवं रजत चढ़ावे की शुद्धता जांचने तथा उनके प्रबंधन की व्यवस्था पहले की तरह निरंतर जारी रहेगी। न्यासी मंडल ने इस व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया।चढ़ावा राशि के प्रबंधन को लेकर भारतीय स्टेट बैंक के साथ हुए समझौते के अंतर्गत बैंक की जिम्मेदारियों और उनके निर्वहन में सामने आई त्रुटियों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। न्यासी मंडल ने इस मामले में बैंक की प्रतिक्रिया और अपेक्षित गंभीरता के अभाव पर असंतोष व्यक्त किया। इसके बाद न्यास की वित्त समिति को बैंक के साथ भविष्य के संबंधों और मानक प्रक्रियाओं की समीक्षा कर आवश्यक निर्णय लेने के निर्देश दिए गए।बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई। चयन समिति ने बताया कि इस पद के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके कारण सभी आवेदनों का गहन परीक्षण करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। समिति ने चयन प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक माह का अतिरिक्त समय मांगा, जिसे विषय की गंभीरता को देखते हुए स्वीकार करने पर विचार किया गया।न्यास ने स्पष्ट किया कि श्रीराम मंदिर से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं में पारदर्शिता, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। आगामी श्रावण मास में बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया जाएगा।

ओमैक्स सिटी चोरीकांड का खुलासा, बिजनौर पुलिस ने शातिर चोर को दबोचा

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। राजधानी के बिजनौर थाना क्षेत्र स्थित ओमैक्स सिटी में बंद मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपये के जेवरात और नकदी चोरी करने की घटना का पुलिस ने सफल खुलासा करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी का सामान, नकदी और अन्य वस्तुएं बरामद की गई हैं, जबकि उसका एक साथी अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है।पुलिस के अनुसार 19 जुलाई 2026 को ओमैक्स सिटी निवासी गर्विता सिंह ने बिजनौर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि अज्ञात चोर उनके बंद मकान का ताला तोड़कर घर में रखे जेवरात, नकदी और अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए। शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई।घटना के खुलासे के लिए पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के निर्देशन में दो विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया। टीमों ने आसपास लगे लगभग 40 से 50 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का गहन विश्लेषण किया। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने बुधवार को औरंगाबाद अंडरपास से न्यू गुडौरा जाने वाली शहीद पथ की सर्विस रोड से सुनील (41 वर्ष) निवासी कठौता, थाना विभूतिखंड को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने अपने साथी शंकर के साथ मिलकर तीन दिन पहले ओमैक्स सिटी के एक बंद मकान की रेकी की थी। रात के समय दोनों ने मकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और जेवरात तथा नकदी चोरी कर ली। इसके बाद दोनों ने चोरी का सामान आपस में बांट लिया। आरोपी ने बताया कि वह चोरी के सामान को बेचने की फिराक में था, तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया।जांच में सामने आया कि आरोपी और उसका साथी बंद पड़े मकानों की पहले रेकी करते थे और फिर रात के समय ताला तोड़कर नकदी, जेवरात तथा अन्य कीमती सामान चोरी कर लेते थे। बाद में चोरी का माल बेचकर आर्थिक लाभ कमाते थे।गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से एक रागा टाइटन कंपनी की महिलाओं की घड़ी, 3,036 रुपये नकद तथा पांच भारतीय और विदेशी सिक्के बरामद किए गए हैं। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता की एक अतिरिक्त धारा भी बढ़ाई गई है।पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी सुनील के खिलाफ पहले भी गाजीपुर थाने में चोरी और चोरी का माल रखने सहित कई मुकदमे दर्ज हैं।

हिंदू राष्ट्र क्यों वांगचुक जैसे 'कॉकरोच' की सुने?

बेचारे सोनम वांगचुक! सांस मोदी के हिंदू राष्ट्र में ले रहे हैं बावजूद इसके माने बैठे हैं कि 'जनमत को जागरूक करना और सत्ता में बैठे लोगों को समझाना, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं'। बारह वर्षों के अनुभवों में वांगचुक इतना भी नहीं समझ पाए कि मौजूदा हिंदू राष्ट्र के सिक्के के दो पहलू नहीं हैं। उसे इधर पलटिए या उधर, दोनों तरफ एक ही चेहरा है- नरेंद्र मोदी का। वही भक्तों के कलियुगी भगवान है। तभी हिंदू मानस में भगवान से जवाब-तलब नहीं होता, केवल पूजा, दर्शन और भक्ति होती है। तो कौन सा जनमत, कैसी जागरूकता और कैसी जवाबदेही? इस सत्य का सबूत हजार साला गुलामी भी है। राम मंदिर टूटा, आक्रमण हुए, अपमान और पराधीनता का लंबा दौर बीता, लेकिन बहुसंख्यक हिंदू समाज ने कभी अपने आराध्य से यह प्रश्न नहीं किया कि 'आपके रहते यह सब क्यों हुआ' न ही उसके भीतर. दिमाग में यह आत्ममंथन बना कि हम हर संकट का समाधान स्वयं बनने के बजाय किसी भगवान, किसी अवतार, किसी उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा में क्यों बैठे रहते हैं? इक्कीसवीं सदी के कथित हिंदू राष्ट्र का भी यही सत्य है। हिंदू अब नागरिक नहीं भीड़ और भक्त में कनवर्ट है। इसलिए क्योंकि नागरिक सवाल पूछता है, जवाबदेही मांगता है। वह सत्ता को अपने प्रति उत्तरदायी मानता है। जबकि भक्त प्रश्न नहीं करता; वह आस्था में जीता है और मोदी के हर निर्णय को भगवान की लीला माने रहता है।

इसलिए सोचें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सौ सालों के चाल, चेहरे, चरित्र ने हिंदुओं को कैसा 'अवतार' दिया? सदियों से किसी उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा करते समाज के सामने अंततः नरेंद्र मोदी ऐसे स्थापित हुए कि वे या तो भगवान हैं, या मोदी ही भारत और भारत ही मोदी है। मोदी के हिंदू राष्ट्र में उन्ही की, अकेली की एक केंद्रित सत्ता है, जिसके सामने राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, संसद और भाजपा जैसी राजनीतिक पार्टी सभी गौण है। मोहन भागवत हों या अमित शाह, राजनाथ सिंह हों या नितिन गडकरी; चुनाव आयोग हो, न्यायपालिका हो, मीडिया हो या नौकरशाही- सत्ता का पूरा तंत्र मोदी के रचित तीर्थ (दिल्ली में बने नए प्रधानमंत्री महल, नई दफ्तरी इमारतों, कथित तीर्थ) की परिक्रमा करता होता है। कृपा, वैधता, प्रतिष्ठा और राजनीतिक भविष्य सभी का मालिक एक अकेले नरेंद्र मोदी। वैसे कलियुगी हिंदू इसी लायक है भी। आखिर हम मानते भी है कि जैसी प्रजा वैसा राजा। तब भला आज की दैवीय व्यवस्था में लोकतंत्र, जनमत, जागरूकता और जवाबदेही जैसे शब्दों का मूल्य कौड़ी भर भी होगा? कतई नहीं। नागरिक की जगह अब भक्त है और संस्थाओं की जगह व्यक्ति पूजा है तो सत्ता से प्रश्न पूछना या जवाबेदही की उम्मीद करना बेवकूफी वाली बातें हैं। ध्यान है पर्यावरणविद् और पूर्व आईआईटी प्रोफेसर जीडी अग्रवाल का नाम। बेचारे ने संन्यास लेकर स्वामी ज्ञानस्वरूप सानंद का नाम धारा और गंगा को अविरल-निर्मल रखने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे। 111 दिनों तक जीवन दांव पर लगाने के बाद 11 अक्टूबर 2018 को ऋषिकेश के एम्स में दम तोड़ा। याद करें उनके निधन पर मोदी और उनकी सत्ता, संघ, भाजपा, साधु-संत, गंगा भक्तों. जनमत में किसी के भी आंसू नहीं निकले! इसलिए दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20-21 दिनों से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक का हिंदू राष्ट्र में जीरो अर्थ है। वे हिंदू अभिभावकों के बच्चों, देश की नई पीढ़ी के भविष्य के ठगी करने वाली नीट परीक्षा जैसी व्यवस्थाओं के खिलाफ कितना ही आंदोलन कर ले उनके लिए हिंदुओं की भीड़ नहीं जुटनी है। जो जुटी है या जुट रही है वह पहले से ही कॉकरोच का तमगा पाए हुए है। उन्हें चप्पल मार कर दबाया जाता है। कर्नाटक के एक अभिनेता प्रकाश राज ने जंतर मंतर जा कर बोला कि यह लड़ाई युवा छात्रों और देश के भविष्य की है व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए है। पर युवा छात्रों की भीड़ भी जब जंतर-मंतर नहीं पहुंची तो किसके लिए कौन सी लड़ाई? जाहिर है भगवान और भक्तों के नए भारत में लड़ाई संभव नहीं है। पिछले बारह वर्षों में बार-बार उभरे पैटर्न पर गौर करें। क्या हुआ है? न देखो, न सुनो, न जवाब दो और बस दर्शन, प्रवचन और चौबीसों घंटे झूठ बोलो। चुनाव जीतने की लीला को झूठ-फरेब से पकाते जाओ। लोकतंत्र, मर्यादा, असहमति की तमाम बाते भाड़ में। गंगा बचाने का अनशन हो या छात्रों, किसानों के साथ खिलवाड़ में आंदोलन हो पहले तो अनदेखी करो। बात ज्यादा बढ़े तो उसे बदनाम करो। फिर उसे किसी राजनीतिक साजिश, विदेशी एजेंडा, खालिस्तानी, अर्बन नक्सल, टुकड़े-टुकड़े गैंग या विपक्ष, कॉकरोचों के खाते में डाल दो। ऐसा किसान आंदोलन के समय हुआ तो अब परीक्षाओं में धांधली के वाकिये में भी है। किसान, पहलवान, मणिपुर की पीड़ति महिलाएं, प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी छात्र और वांगचुक के मौजूदा मसले सब हिंदू राष्ट्र में वैसे ही हैंडल होते हुए है जैसे हिंदुओं की गुलामी के हजार सालों में हुआ। तब अंग्रेज हाकिमों का राजकाज तथा व्यवहार गुलाम प्रजा की रियलिटी में बना हुआ था।

कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च से सुलगते सवाल और राजनीतिक निहितार्थ

देखा जाए तो इस आंदोलन की प्रमुख मांगों में नीट पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं पर कार्रवाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार की जवाबदेही, कुछ नेताओं द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

कमलेश पांडे

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का ₹संसद चलो₹ आह्वान केवल एक विरोध मार्च नहीं, बल्कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की एक राजनीतिक रणनीति है। खासकर जिस तरह से इस आंदोलन को छात्र आंदोलन का स्वरूप दिलवाया जा चुका है, वह डीप स्टेट के इशारे पर बनी विपक्ष की शातिर सरकार घेरो रणनीति का कमाल भी करार दिया जा रहा है। देखा जाए तो संसद के मानसून सत्र के दौरान गत 20 जुलाई को जंतर-मंतर से संसद की ओर मार्च करने के दौरान बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे और कूच किया, वह बिल्कुल संगठित राजनीतिक आंदोलन के तर्ज पर हुआ।

मजे की बात तो यह कि संसद के निकट पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जो पूर्व प्रायोजित झड़प हुई और उसके बाद हालात नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, इससे यह संसद मार्च राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बन गया। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स और अखबारों के दफ्तरों में इससे जुड़े कई नीतिगत सवालों पर भी बहस होने लगी। सोशल मीडिया पर जहां सरकार विरोधी भड़काऊ वीडियो वायरल होने लगे, वहीं सत्ताधारी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी आंदोलनकारियों की कारगुजारियों के वीडियो साझा कर दिए, जिससे लोगों की सहानुभूति पुलिस और सरकार के साथ बनी रही।

यदि संसद मार्च के घटनाक्रमों पर संतुलित नजर डालें तो यही प्रतीत होता है कि जब बड़ी संख्या में सीजेपी (CJP) समर्थक ₹संसद चलो₹ मार्च के लिए जंतर-मंतर से संसद की ओर बढ़े, तो भले ही उनकी मुख्य मांगें शिक्षा सुधार, परीक्षा-पत्र लीक और जवाबदेही था, लेकिन इरादे तोड़फोड़ वाले और खतरनाक थे, अन्यथा पुलिस को बल प्रयोग नहीं करना पड़ता। चूंकि संसद के मानसून सत्र के दौरान माननीयों की सुरक्षा के दृष्टिगत दिल्ली पुलिस ने व्यापक बैरिकेडिंग की थी, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को रोका, हिरासत में लिया तथा कुछ स्थानों पर आंदोलनकारियों द्वारा उपद्रव करने के बाद आंसू गैस और बल प्रयोग की घटनाएं सामने आईं। इससे अफरातफरी मच गई।

देखा जाए तो इस आंदोलन की प्रमुख मांगों में नीट (NEET) पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं पर कार्रवाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार की जवाबदेही, कुछ नेताओं द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, आंदोलन से जुड़े लोगों के साथ संवाद आदि हैं, लेकिन जो उत्पात दिखाई-सुनाई दिया, वह विपक्षी संस्कार नहीं तो क्या है? फिर भी, केंद्र सरकार ने आंदोलन के प्रतिनिधियों से बातचीत की पहल भी की, जो टकराव के बीच संवाद की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा सकता है। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा ने सरकारी प्रतिनिधि के तौर पर CJP प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की और मांगपत्र ग्रहण किया। बावजूद इसके आंदोलनकारी अपनी मांगों पर कायम हैं।

सवाल है कि संसद मार्च के क्रम में जो कुछ गड़बड़ हुआ, क्या वह लोकतांत्रिक है, सही था या गलत? तो जवाब होगा कि युवाओं का शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा की निष्पक्षता जैसे मुद्दों पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ उठाना लोकतंत्र का वैध हिस्सा है। वहीं, सरकार द्वारा आंदोलनकारियों से बातचीत शुरू करना भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप कदम है। फिर भी संसद मार्च के दौरान आंदोलनकारियों की ओर से कुछ कुछ गलत हुआ जो अनुचित लगा। यदि प्रदर्शनकारियों ने निषिद्ध क्षेत्र में जबरन प्रवेश करने या बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, तो वह कानून-व्यवस्था की दृष्टि से उचित नहीं माना जाएगा।

वहीं, यदि पुलिस ने आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया या शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर अनावश्यक कार्रवाई हुई, तो उसकी भी निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय होनी चाहिए। हालांकि, इस पर अलग-अलग पक्षों के अपने अपने दावे हैं और सभी तथ्यों के गोलमोल जवाब ही मिले हैं, जिनपर एतबार करना मुश्किल है क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, जिसका अंतिम सत्यापन अभी होना बाकी है, कई अनकही कहानियां गढ़ रहे हैं। इससे सरकार सांसत में है और विपक्ष तरह-तरह के आरोप लगाकर सिस्टम की मुश्किलें बढ़ा रहा है। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं कि लोकतांत्रिक समाधान का सर्वोत्तम रास्ता संवाद और कानून के दायरे में रहकर समस्या का समाधान है।

भले ही किसी भी लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन और अपनी मांगें रखना नागरिकों का अधिकार है, लेकिन इस संसद मार्च के क्रम में देश की राजधानी नई दिल्ली के हृदय स्थल पर, जिस प्रकार की हिंसा, तोड़फोड़, सार्वजनिक व निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना या सुरक्षा बलों से टकराव की जो प्रवृति दिखाई दी, वह विपक्षी दलों का परोक्ष कुचक्र नहीं तो क्या है? आखिर इस देशद्रोही प्रवृति को कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

इसी प्रकार, यदि पुलिस बल का प्रयोग आवश्यकता से अधिक हुआ हो, तो उसकी भी निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए। सवाल है कि क्या स्थानीय जिलाधिकारी और डीसीपी के पास छात्र समूह को काबू में रखने की कोई स्पष्ट रणनीति नहीं थी? और यदि थी तो फिर इतना सबकुछ कैसे हुआ? वहीं कोई पुलिस कर्मी कैसे पिट गया और घायल हुआ? आखिर किसी दुकानदार को तोड़-फोड़ का सामना क्यों और कैसे करना पड़ा? जनपथ बाजार की सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त क्यों नहीं किए गए थे। वहीं, अनियंत्रित युवा भीड़ क्यों जुटने दी गई और उनको काबू में रखने के लिए व्यापक बंदोबस्त क्यों नहीं किये गए थे?

कॉकरोच जनता पार्टी के ₹संसद चलो₹ आह्वान के राजनीतिक मायने केवल एक विरोध मार्च तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह भारतीय राजनीति में युवाओं के असंतोष, डिजिटल आंदोलन और पारंपरिक दलों के प्रति अविश्वास का प्रतीक बनकर उभरा है। हालांकि CJP स्वयं को व्यंग्यात्मक (satirical) आंदोलन बताता है, लेकिन इसके मुद्दे गंभीर राजनीतिक प्रश्न उठाते हैं।

यही वजह है कि राजनीतिक दृष्टि से इसके कई मायने निकाले जा रहे हैंः- पहला, संसद के मानसून सत्र के पहले दिन दबाव की राजनीति। दूसरा, युवाओं और प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थियों के असंतोष को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का प्रयास। तीसरा, विपक्ष के लिए सरकार को घेरने का अवसर और चौथा, सरकार के लिए कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए आंदोलनकारियों से संवाद की चुनौती आदि।

हालांकि, इसके प्रमुख राजनीतिक संकेत इस प्रकार हैंः एक, युवा असंतोष का राजनीतिक रूपांतरणः बेरोज़गारी, परीक्षा-पत्र लीक, शिक्षा व्यवस्था और राजनीतिक जवाबदेही जैसे मुद्दों को लेकर नाराज़गी को संगठित करने का प्रयास दिखाई देता है। दो, डिजिटल से सड़क तकः सोशल मीडिया पर शुरू हुआ अभियान अब वास्तविक जन-प्रदर्शन में बदलता दिख रहा है, जो यह संकेत देता है कि ऑनलाइन असंतोष भी राजनीतिक दबाव का माध्यम बन सकता है।

व्यंग्य

संसद या सियासी अखाड़ा?

विचारधारा, नीति, कार्यक्रम, चुनाव घोषणापत्र आदि का आज क्या औचित्य रह गया है? अगर ये राजनीति के प्रेरक तत्व ना रहें, तो फिर पहलवानी के अखाड़े और संसद के बीच क्या फर्क रह जाएगा?

मानसून सत्र की शुरुआत के साथ संसद का नज़ारा कुछ बदला नजर आएगा। यह संभवतः पहला मौका है, जब बिना चुनाव हुए सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के संख्या बल में गुणात्मक बदलाव हुआ दिखेगा। बजट सत्र के बाद तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव) बड़ी टूट-फूट हो चुकी है, जबकि एनसीपी (शरद पवार गुट) के रुख में बदलाव के संकेत मिले हैं। इससे बिना नया जनादेश आए ही सत्ताधारी एनडीए मजबूत हो गया है। इस हद तक कि अभी दो महीने पहले लोकसभा सीटों के परिसीमन के मकसद से लाया गया जो विधेयक गिर गया था, सत्ता पक्ष उसे फिर से लाने की तैयारी में दिखा है।

इसी तरह विवादास्पद विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक-2025 और गिरफ्तारी होने पर 30 दिन के अंदर मुख्यमंत्री/ मंत्री पद खत्म करने का प्रावधान करने वाले विधेयक को भी लाने की चर्चा थी (जिसका इरादा शायद टाल दिया है)। पिछले सत्र तक इन विधेयकों के पारित होने की संभावना बेहद कमजोर थी। अभी भी इनके लिए सरकार संख्या बल का पूरा इंतजाम नहीं कर पाई है, लेकिन कुछ और जोड़-तोड़ में कामयाब रही, तो इनके पारित होने की संभावना बन सकती है। मगर यही समस्या है। वह संभावना 2024 में आए जनादेश की भावना के विपरीत होगी। मुद्दा है कि दांव-पेच से जनादेश की भावना को इस तरह धता बताने का चलन आम हो जाता है, तो फिर विचारधारा, नीति, कार्यक्रम, चुनाव घोषणापत्र आदि का क्या औचित्य रह जाएगा?

ये राजनीति के प्रेरक तत्व ना रहें, तो फिर पहलवानी के अखाड़े में होने वाली जोर-आजमाईश और संसदीय प्रक्रियाओं के बीच क्या फर्क रहेगा? क्या उसके बाद भी संसद को बहस के जरिए अधिकतम संभव सहमति निर्माण का मंच माना जा सकेगा? दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में इन प्रश्नों के उत्तर लगातार नकारात्मक होते गए हैं। संसद शोर, हंगामे, वॉकआउट, बहिष्कार, और कई बार तो शारीरिक बल के जरिए झड़पों का स्थल बनती चली गई है। नतीजतन, अधिवेशनों से पहले गंभीर बहस से ज्यादा अपेक्षा टकराव और तू तू-मैं- मैं की रहने लगी है। मानसून सत्र के पहले भी राजनीतिक क्षितिज पर यही माहौल हावी नजर आया है।

ब्लॉग

भारत में खो गई है जवाबदेही?

श्रुति व्यास

शनिवार को सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ, उसे देखते हुए पहली बार लगा कि भारत में केवल राजनीति नहीं बदली है, जवाबदेही भी बदल गई है।

1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को चुनावी अनियमितताओं का दोषी ठहराते हुए उनका चुनाव खारिज किया था। फैसला सीधे प्रधानमंत्री के खिलाफ था। इंदिरा गांधी ने उसे स्वीकार करने के बजाय आपातकाल लगाया। वह लोकतंत्र का सबसे अंधकारमय अध्याय था, लेकिन उसमें एक राजनीतिक सच्चाई भी थी। आरोप प्रधानमंत्री पर था और पूरा देश जानता था कि जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री की है। सत्ता बचाने का उनका तरीका लोकतांत्रिक नहीं था, लेकिन जवाबदेही का अंतिम पता किसी को खोजने की जरूरत नहीं थी। भारत का हर नागरिक जानता-समझता था

चौदह वर्ष बाद यही कसौटी राजीव गांधी के सामने आई। वे ₹मिस्टर क्लीन₹ की छवि लेकर सत्ता में आए, लेकिन बोफोर्स विवाद उनकी पूरी राजनीतिक पहचान पर छा गया। हालांकि अदालत कभी यह साबित नहीं कर सकी कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से रिश्वत ली थी। फिर भी जनता ने राजनीतिक फैसला दे दिया। प्रधानमंत्री के इतने निकट हुआ सौदा प्रधानमंत्री की राजनीतिक जिम्मेदारी भी बना। और1989 में उसकी कीमत उन्हें सत्ता गंवाकर चुकानी पड़ी।

फिर मनमोहन सिंह आए। उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी पर शायद ही किसी ने सवाल उठाया हो। लेकिन लोकतंत्र व्यक्ति की नहीं, पद की जवाबदेही भी तय करता है। 2जी स्पेक्ट्रम और कोयला आवंटन विवाद उनके कार्यकाल में सामने आए। लंबे समय तक कोयला मंत्रालय स्वयं उनके पास था। इसलिए ₹मुझे जानकारी नहीं थी₹ जैसी सफाई राजनीतिक रूप से टिक नहीं सकी। किसी ने यह नहीं कहा कि उन्होंने अपनी जेब भरी, लेकिन इतना पर्याप्त था कि विवाद प्रधानमंत्री कार्यालय की चौखट तक पहुँच चुका था। 2014 में उसकी राजनीतिक कीमत कांग्रेस ने चुकाई।

इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह—तीनों एक-दूसरे से बिल्कुल अलग थे। फिर भी उनमें एक समानता थी। उनके आसपास पैदा हुआ बड़ा विवाद अंततः प्रधानमंत्री तक पहुँचता था। कभी प्रतिष्ठा जाती थी, कभी सरकार, कभी दोनों। उस समय जवाबदेही को सत्ता के शिखर (प्रधानमंत्री पद) तक पहुँचने में ज्यादा समय नहीं लगता था।

यही भारतीय लोकतंत्र का विकास था। उपलब्धि थी। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक आदत थी। लोकतंत्र में सरकार का चेहरा ही उसकी अंतिम जवाबदेही भी होता था।

यहीं मुझे लगता है कि पिछले दशक में सबसे बड़ा बदलाव आया है।

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का दशक विवादों से खाली नहीं रहा। किसानों का लंबा आंदोलन हुआ। देश की शीर्ष महिला पहलवानों ने सत्तारूढ़ दल के प्रभावशाली सांसद के खिलाफ संघर्ष किया। प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र बार-बार लीक हुए। भर्ती प्रक्रियाएँ संदेह के घेरे में आईं। लद्दाख में असंतोष बना। कई मौकों पर नागरिकों ने सरकार से जवाब माँगा।

लेकिन इन सबमें एक बात समान रही। विवाद जंतर-मंतर, दिल्ली के प्रवेश दरवाजों तक और सरकार तक भी पहुँचे, मगर प्रधानमंत्री तक नहीं। यही इस दौर की सबसे असाधारण राजनीतिक विशेषता है।

यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विरोध करने वाले वही वर्ग थे जिन्हें नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीति के केंद्र में रखा था। अच्छे दिनों के वायदे में किसान राष्ट्र की रीढ़ बताए गए थे। युवाओं को भारत की सबसे बड़ी शक्ति कहा गया। 'डेमोग्राफिक डिविडेंड' केवल आर्थिक अवधारणा नहीं, बल्कि पूरे शासनकाल की राजनीतिक कथा थी।

2018 में तुमकुरु के एक युवा सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यदि समाज के लिए 'विद्यार्थी देवो भव' मंत्र है, तो उनके लिए 'युवा शक्ति देवो भव' मंत्र है।

फिर प्रश्नपत्र लीक का दौर आया। करोड़ों युवाओं ने केवल परीक्षाएँ नहीं खोईं; उन्होंने व्यवस्था पर अपना भरोसा भी खोया। स्वाभाविक अपेक्षा थी कि जिसने युवाओं को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बताया, वही उनके सबसे कठिन समय में सबसे पहले दिखाई देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

पहले सन्नाटा रहा। फिर प्रतीक्षा। फिर वही मंत्री अपने पद पर बने रहे जिनके विभाग पर सवाल उठ रहे थे। धीरे-धीरे शिकायत से अधिक चर्चा शिकायत करने वालों पर होने लगी। भारतीय राजनीति में यह नई रणनीति नहीं है। जब किसी प्रश्न का उत्तर कठिन हो, तो बहस को प्रश्न से हटाकर विरोध पर ले जाइए। धीरे-धीरे मूल प्रश्न ही धुँधला पड़ जाता है।

यही बात दूसरे विवादों में भी दिखाई देती है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश की सात शीर्ष महिला पहलवानों ने आरोप लगाए। लखीमपुर खीरी में चार किसानों की मौत के बाद भी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी लंबे समय तक पद पर बने रहे। राष्ट्रीय परीक्षा विवाद में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर सवाल उठे। हर बार राजनीतिक बहस किसी मंत्री, किसी सांसद या किसी संस्था तक पहुँची, लेकिन शायद ही कभी प्रधानमंत्री तक पहुँची।

पहले ऐसा नहीं होता था। इनमें से हर विवाद प्रधानमंत्री कार्यालय के इतना निकट था कि भारतीय राजनीति के पहले के दौर में वह एक-दो सीढ़ियाँ और ऊपर चढ़ता। अब वह जैसे अंतिम सीढ़ी पर पहुँचने से पहले ही रुक जाता है।

इसका एक उत्तर राजनीतिक प्रबंधन में है। हर सरकार विवादों को नियंत्रित करने की कोशिश करती है। जाँच बैठती है, समय लिया जाता है, बहस का केंद्र बदला जाता है। मोदी सरकार ने यह कला असाधारण दक्षता से सीखी है। लेकिन केवल राजनीतिक प्रबंधन पर्याप्त उत्तर नहीं है।

उसके लिए नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक छवि को भी समझना होगा। उनके पीछे कोई राजनीतिक वंश नहीं है। रिश्तेदारों के लाभ उठाने की सार्वजनिक कहानियाँ नहीं हैं। निजी संपत्ति बढ़ाने की व्यापक धारणा भी नहीं है। उन्होंने स्वयं को बार-बार 'फकीर' कहा है। बड़ी संख्या में लोग इस छवि पर विश्वास करते हैं। और लोकतंत्र में विश्वास केवल नेता की छवि नहीं बदलता, जवाबदेही का रास्ता भी बदल देता है। फिर भी यहीं सबसे बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है।

यदि प्रधानमंत्री वास्तव में अपने आसपास के विवादों से पूरी तरह अछूते हैं, तो फिर वही विवाद बार-बार बने क्यों रहते हैं? जो नेता व्यक्तिगत रूप से सबसे सुरक्षित हो, उसके लिए विवादित सहयोगियों से दूरी बनाना, उन्हे हटाना सबसे आसान होना चाहिए। वास्तविक अधिकार वही है जो अपने लोगों पर भी लागू हो सके।

लेकिन बार-बार उलटा दिखाई देता है। विवाद समाप्त करने के बजाय उन्हें साथ लेकर चलने का निर्णय लिया जाता है।

संभव है इसका उत्तर नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत निष्कलंकता से कम और उनकी तथा अमित शाह की राजनीतिक गणित से अधिक जुड़ा हो। हर नेता निष्ठाओं के नेटवर्क के सहारे शासन करता है। किसी प्रभावशाली सहयोगी को हटाना केवल नैतिक निर्णय नहीं, राजनीतिक जोखिम भी है। शक्ति-संतुलन बदलता है, संगठन को संदेश जाता है और समीकरण प्रभावित होते हैं। इसलिए विवाद को सह लेना, कई बार उसे समाप्त करने से सस्ता पड़ता है।

या फिर बात इससे भी आगे की है। संभव है नेतृत्व को अब यह भरोसा हो गया हो कि विवाद, आंदोलन, असंतोष, गुस्सा शीर्ष नेतृत्व तक राजनीतिक नुकसान पहुँचाने की क्षमता खो चुके हैं। नरेंद्र मोदी और उनके समर्थकों के बीच बना भावनात्मक संबंध इतना मजबूत हो चुका है कि बड़ी संख्या में मतदाता प्रधानमंत्री और उनके नाम पर शासन करने वालों के बीच स्पष्ट अंतर कर लेते हैं। सरकार से शिकायत हो सकती है, किसी मंत्री से नाराज़गी भी हो सकती है, लेकिन उसकी राजनीतिक जिम्मेदारी स्वतः प्रधानमंत्री तक नहीं पहुँचती।

यहीं से वह प्रश्न जन्म लेता है जो शायद नरेंद्र मोदी से भी बड़ा है।

लोकतंत्र का तब क्या होता है, जब जवाबदेही अपनी पूरी यात्रा करना बंद कर दे?

स्वतंत्र भारत के अधिकांश इतिहास में राजनीतिक जिम्मेदारी अंततः सत्ता के सर्वोच्च पद तक पहुँच जाती थी। कभी वह प्रक्रिया अपूर्ण थी, कभी कठोर, कभी अन्यायपूर्ण भी। लेकिन यात्रा पूरी होती थी।

आज असहमति अब भी है। आंदोलन भी हैं। सवाल भी हैं। बदला है तो केवल उनका रास्ता।

शनिवार को सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ, उसने मुझे इसी बदलाव का एहसास कराया। प्रश्न उठा, लेकिन वह भी अंततः उसी जगह जाकर ठहर गया जहाँ पिछले कई वर्षों से दूसरे प्रश्न ठहरते आए हैं।

शायद यही हमारे समय का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवर्तन है। भारत में विवाद खत्म नहीं हुए हैं। विरोध भी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन जवाबदेही जैसे अपनी आख़िरी सीढ़ी तक पहुँचना भूल गई है।

यह केवल एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री की कहानी नहीं है। यह उस लोकतांत्रिक मनोविज्ञान की कहानी है जिसमें सत्ता का सर्वोच्च पद पहले की तरह सबसे बड़ा उत्तरदायित्व नहीं रह गया है।

कभी भारतीय लोकतंत्र में जवाबदेही का रास्ता सीधा प्रधानमंत्री के दरवाज़े तक जाता था। आज वह रास्ता जैसे कहीं बीच में मुड़ जाता है। शायद यही कारण है कि मोदी वर्षों की कहानी केवल नरेंद्र मोदी की कहानी नहीं रह जाती; वह भारतीय लोकतंत्र की बदलती प्रकृति की कहानी बन जाती है। उसमें असहमति जीवित है, प्रश्न भी जीवित हैं, लेकिन उन प्रश्नों का अंतिम पता अब पहले जितना निश्चित नहीं रह गया है।

चढ़ावा चोरी से भी लोग शर्मिंदा नहीं... इलाहाबाद हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- भ्रष्टाचार रोकने के लिए मृत्युदंड पर विचार की जरूरत

आर्यावर्त संवाददाता

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण और भ्रष्टाचार पर सुनवाई के दौरान बेहद कड़ी टिप्पणियां करते हुए कहा कि देश में भ्रष्टाचार अब सामान्य बात बन चुकी है। कोर्ट ने कहा कि राम मंदिर के लिए आए दान में चोरी का मामला भी लोगों को शर्मिंदा नहीं कर सका, जो ईमानदारी के सबसे निचले स्तर को दर्शाता है। यदि सरकार वास्तव में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहती है तो कानून में संशोधन कर गंभीर मामलों में मृत्युदंड तक का प्रावधान करने पर विचार करना चाहिए।

जस्टिस अतुल श्रीधरन ने ये टिप्पणियां हमीरपुर के कैफुद्दीन समेत अन्य याचिकाओं की सुनवाई के दौरान अपने फैसले में दर्ज कीं। याचिकाकर्ताओं ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक और संरक्षण की मांग की थी। इस मामले की सुनवाई वाली खंडपीठ में जस्टिस सिद्धार्थनंद भी शामिल थे, जिन्होंने कुछ बिंदुओं पर अलग राय व्यक्त की।

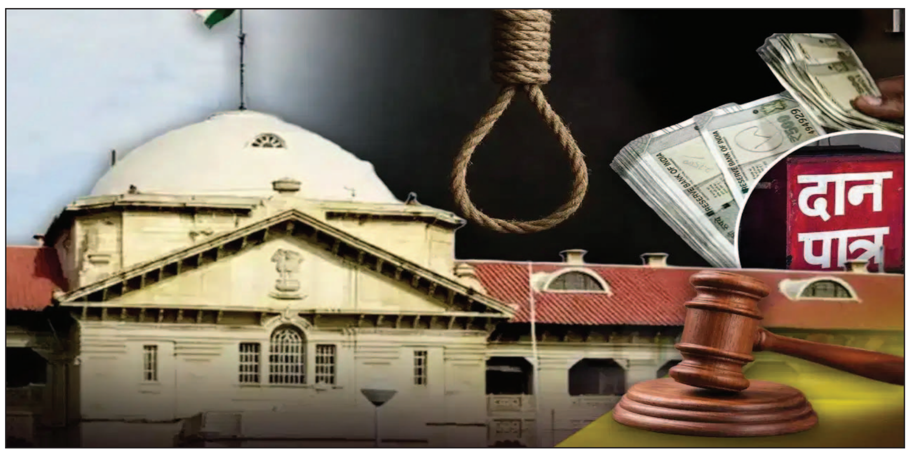

हाई कोर्ट ने कहा कि नगर निगम और अन्य प्राधिकरणों के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध निर्माण खड़े हो जाते हैं। अधिकारी रिश्वत लेकर आंखें बंद कर लेते हैं और जब कार्रवाई होती है तो उसका खामियाजा आम खरीदार को भुगतना पड़ता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अवैध निर्माण कराने वाले बिल्डरों के साथ-साथ उन्हें संरक्षण देने वाले भ्रष्ट अधिकारियों को भी कानून के अनुसार सख्त सजा मिलनी चाहिए।

भ्रष्टाचार से बढ़ रही अमीर-गरीब की खाई : HC

भ्रष्टाचार से बढ़ रही असमानता का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार के कारण कुछ लोगों के हाथों में अवैध रूप से संपत्ति इकट्ठी हो रही है, जिससे अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार बढ़ रही है। यदि समय रहते इस पर प्रभावी रोक नहीं लगी तो भविष्य में सामाजिक असंतोष और गंभीर हालात पैदा हो सकते हैं।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी का किया जिक्र

अपने 51 पेज के फैसले में जस्टिस अतुल श्रीधरन ने कहा कि राम मंदिर में दान चोरी का विवाद ऊंट की पीठ पर आखिरी तिनका साबित हुआ। कोर्ट ने कहा कि यदि इतने संवेदनशील धार्मिक स्थल पर दान में हुई चोरी से भी समाज विचलित नहीं होता, तो यह ईमानदारी के गिरते स्तर का गंभीर संकेत है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2025 की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया और कहा कि 182 देशों में भारत 91वें स्थान पर है, लेकिन इसके बावजूद भ्रष्टाचार को लेकर समाज में अपेक्षित संवेदनशीलता दिखाई नहीं देती। जस्टिस श्रीधरन ने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से जुड़ा हाल का विवाद, सब्र का बांध टूटने जैसा है। उन्होंने यह चिंता भी जताई कि समाज में भ्रटाचार ने इतना जड़ जमा लिया है कि अब सरकार को इस तरह के मामले के दोषियों को मृत्युदंड देने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक कानून-1988 में संशोधन करने पर विचार करना चाहिए।

बुलडोजर कार्रवाई पर भी अहम निर्देश

कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद 2 साल तक उसका मकान ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी मकान में 3 साल या उससे अधिक समय से रह रहा है, तो ध्वस्तिकरण से एक साल पहले नोटिस देकर वैकल्पिक व्यवस्था का अवसर दिया जाना चाहिए। हालांकि, इस बिंदु पर जस्टिस सिद्धार्थनंद ने असहमति जताते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट किसी निश्चित समय-सीमा, जैसे 2 साल, तय नहीं कर सकता। उनका मत था कि ऐसा प्रावधान भविष्य में आरोपी द्वारा कार्रवाई से बचने के लिए एफआईआर का दुरुपयोग करने का माध्यम बन सकता है।

राहुल गांधी की गिरफ्तारी पर कांग्रेस का सत्याग्रह

जौनपुर। नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को नयी दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के सामने गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ आक्रोशित पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष बुधवार को धरना-प्रदर्शन कर सत्याग्रह आंदोलन किया। उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार को तानाशाह और निरंकुश तथा लोकतंत्र विरोधी करार देते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार की नाकामियों के कारण देश में भय और भ्रष्टाचार फैला गया है। सत्याग्रह आंदोलन में सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव सत्यवीर सिंह ने कहा कि अपने अधिकार और पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे देश के युवाओं को लाठियो से बर्बरतापूर्वक पीटना ब्रिटिश हुकूमत की यादों को ताजा कर दिया है। डा.राकेश मिश्र , लाल प्रकाश पाल ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं।

विधायक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना कीं टीकाकरण टीमें

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। सदर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक विनोद सिंह ने बुधवार को पशु चिकित्सालय सदर से राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP) के अंतर्गत खुरपका-मुंहपका (एफएमडी) टीकाकरण अभियान के आठवें चरण का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. प्रमोद कुमार शर्मा भी मौजूद रहे।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि 22 जुलाई से 8 सितंबर 2026 तक चलने वाले 45 दिवसीय अभियान के दौरान जनपद के 2,19,020 गोवंशीय एवं 2,35,036 महिषवंशीय पशुओं सहित कुल 4,54,056 पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। चार माह से कम आयु के तथा आठ माह से अधिक गर्भित पशुओं को छोड़कर सभी पात्र पशुओं को टीका लगाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि अभियान के लिए 39 टीमें गठित की गई हैं, जो रोस्टर के अनुसार गांव-गांव जाकर पशुपालकों के घरों पर पशुओं का टीकाकरण करेंगी। टीकाकरण से पहले पशुओं के कान में टैग लगाया जाएगा और टीकाकरण का पूरा विवरण भारत पशुधन ऐप पर अपलोड किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक विनोद सिंह ने पशुपालकों से अपील की कि वे अभियान में सहयोग करते हुए अपने सभी पात्र पशुओं का समय से टीकाकरण अवश्य कराएं। उन्होंने कहा कि पशुधन की सुरक्षा और किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए इस तरह के अभियान बेहद महत्वपूर्ण हैं।

कार्यक्रम में डॉ. नरेंद्र कुमार ओझा, डॉ. चन्द्रसेन गुप्ता, डॉ. जगदीश प्रसाद कुशवाहा, डॉ. राजेश कुमार वर्मा, डॉ. राहुल गुप्ता, डॉ. शैलेन्द्र कुमार सिंह सहित पशुपालन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी एवं पैरावेट/मैत्री उपस्थित रहे।

सुबह बेटे का बर्थडे, मां ने कीर्तन कर बनाई खीर-पूरी... रात में छोटे और बड़े बेटों ने माता-पिता की ले ली जान, बहन बोली- इन्हें मिले सजा-ए-मौत

आर्यावर्त संवाददाता

गाजियाबाद। रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक माना जाता है, लेकिन गाजियाबाद से सामने आई एक घटना ने इस रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। दो बेटों ने अपने ही मां-बाप की बेरहमी से हत्या कर दी। अपने माता-पिता की हत्या के बाद शोक में डूबी एक बहन ने रोते हुए कहा, "ऐसे भाई किसी को न मिलें। जिन्होंने हमारे मम्मी-पापा की जान ले ली। जैसे मेरे भाइयों ने मेरे माता-पिता को मारा है, वैसे ही उन्हें भी उनके किए की सजा मिले।"*

मामला गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र के भीमनगर इलाके का है। पुलिस के अनुसार, 20 जुलाई की रात दो बेटों ने अपने माता-पिता की हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक दंपति की बेटियां दीपिका और ज्योति भी मौके पर पहुंचीं। घर के बाहर लोगों की भीड़ और भारी पुलिस बल तैनात था, जबकि घर के भीतर मातम पसरा हुआ था। पुलिस बेटियों के बयान दर्ज कर रही थी और इस दौरान उनका रो-रोकर बुरा हाल था।

जन्मदिन की खुशियां कुछ ही घंटों में मातम में बदलीं

मृतक गंगाशरण मूल रूप से बुलंदशहर के रहने वाले थे और कई वर्षों से परिवार के साथ गाजियाबाद में रह रहे थे। उनके दो बेटे दीपक और ललित तथा दो बेटियां दीपिका और ज्योति हैं। दोनों बेटों की शादी लॉकडाउन के दौरान हुई थी, लेकिन बाद में इनसे तंग आकर उनकी पत्नियां उन्हें छोड़कर मायके चली गई थीं। पिता गंगाशरण अखबार वितरक थे। पूरा परिवार ग्राउंड फ्लोर पर रहता है, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर किरायेदार रहता है। किरायेदार ने ही पुलिस को खबर दी थी।

घटना वाले दिन छोटे बेटे ललित का जन्मदिन था। उसकी मां विमलेश ने बेटे की लंबी उम्र के लिए पड़ोस की महिलाओं के साथ कीर्तन कराया और घर में खीर-पूरी बनाई। शाम तक घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन रात होते-होते यह खुशी मातम में बदल गई।

शराब पीने को लेकर हुआ विवाद

परिजनों और स्थानीय लोगों के मुताबिक, दोनों भाई शराब के आदी थे और अक्सर नशे की हालत में घर में झगड़ा करते थे। 20 जुलाई की रात भी दोनों शराब पी रहे थे। जब माता-पिता ने इसका विरोध किया तो कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों बेटों ने पहले पिता गंगाशरण पर हमला किया। मां विमलेश बचाने आईं तो उन पर भी हमला कर दिया। दोनों का गला दबाने के बाद उन पर हथौड़े से वार किए गए। गंभीर रूप से घायल दंपति को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

बेटियों ने सुनाई भाइयों की करतूत

मृतक दंपति की बड़ी बेटी दीपिका ने आरोप लगाया कि दोनों भाई लंबे समय से शराब के आदी थे और अक्सर माता-पिता के साथ मारपीट व झगड़ा करते थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि शराब के लिए दोनों ने अपनी मां के सोने के जेवर तक बेच दिए थे। इसके बावजूद माता-पिता हर बार उन्हें माफ कर देते थे और उम्मीद करते थे कि एक दिन वे सुधर जाएंगे।

दीपिका ने कहा कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके अपने सगे भाई ही माता-पिता के कातिल बन जाएंगे। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुटी है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री के स्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट में विभिन्न छात्र संगठनों के बैनर तले बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी डीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए और केंद्र सरकार व शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शनए शिक्षा मंत्री का पुतला फूंकने पर पुलिस से झड़प हुई। छात्र नेता हिरासत में लिये गये। धरने में शामिल वक्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के हालिया बयान से समाज के एक बड़े वर्ग की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री को अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है और उन्हें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए। कलेक्ट्रेट परिसर में काफी देर तक विरोध.प्रदर्शन चलता रहाए जिससे वहां गहमागहमी का माहौल बना रहा। कानून.व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और प्रशासनिक अधिकारी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रहे।

महिला से घर में घुसकर मारपीट

जौनपुर। जलालपुर थाना क्षेत्र के मझगवां कला गांव में मायके आई एक महिला से घर में घुसकर मारपीट और जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। पीड़ति ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। केराकत थाना क्षेत्र के मुर्की निवासी रेहाना पत्नी नूरुल हक ने आरोप लगाया है कि 21 जुलाई की शाम करीब आठ बजे वह अपने मायके मझगवां कला में भाभी सलमा के साथ बातचीत कर रही थीं। तभी गांव का तारीफ पुत्र मेराज अकबर उर्फ नन्हे पुरानी पारिवारिक रंजिश के चलते उनके घर में घुस आया। आरोपी तारीफ ने रेहाना के साथ गाली-गलौज करते हुए हमला कर दिया। विरोध करने पर उसने लाठी-डंडों से मारपीट की, जिससे रेहाना को चोटें आईं। पीड़ति ने यह भी आरोप लगाया है कि इस दौरान आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी।

15 दंगे, 68 तीर्थ स्थलों पर कब्जे... संभल रिपोर्ट में कई बड़े दावे, UP विधानसभा में पेश होगी 450 पन्नों की रिपोर्ट

आर्यावर्त संवाददाता

संभल। 24 नवंबर, 2024 को संभल में हुई हिंसा की जांच करने वाले न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान सदन में पेश की जाएगी। आयोग ने लगभग 450 पन्नों की यह रिपोर्ट पिछले साल 28 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी थी। रिपोर्ट में संभल की सामाजिक और डेमोग्राफिक स्थिति के बारे में कई गंभीर दावे किए गए हैं।

आयोग के अनुसार, पिछले कुछ दशकों में सम्भल के डेमोग्राफिक्स को बदलने की एक व्यवस्थित कोशिश की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आजादी के समय संभल नगरपालिका क्षेत्र में हिंदू आबादी लगभग 45 प्रतिशत थी, जो अब घटकर लगभग 15 प्रतिशत रह गई है। आयोग ने इस गिरावट के मुख्य कारणों के तौर पर लगातार हिंसा, पलायन और सांप्रदायिक घटनाओं की पहचान की है।कथित 'लव जिहाद' और धर्म परिवर्तन का दावा

रिपोर्ट का दावा है कि दंगे, कथित 'लव जिहाद' और धर्म परिवर्तन जैसी गतिविधियों के कारण हिंदू आबादी में कमी आई। इसमें यह भी बताया गया है कि जब हिंदू आबादी 20 प्रतिशत से कम हो गई, तो विदेशी मूल के मुसलमानों और स्थानीय ('देसी') मुसलमानों के बीच टकराव शुरू हो गए। आयोग ने तुर्क समुदाय और धर्म परिवर्तन करने वाले हिंदू मूल के पठानों के बीच विवादों का भी जिक्र किया है।

19 पवित्र कुओं पर कब्जा

जांच रिपोर्ट में पिछले सात दशकों में सम्भल में हुए 15 सांप्रदायिक दंगों का विवरण दिया गया है। इसके अलावा, इसमें 68 तीर्थ स्थलों और 19 पवित्र कुओं पर कथित कब्जे का भी जिक्र है। हरिहर मंदिर का हवाला देते हुए, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वहां बाबर के दौर के सबूत मिले हैं।

आतंकवादी गतिविधियों का खुलासा

अपनी रिपोर्ट में, आयोग ने कुछ आतंकवादी संगठनों की कथित गतिविधियों और आसिम, उर्फ सना-उल-हक की भूमिका पर भी प्रकाश डाला है। रिपोर्ट के अनुसार, उसे अमेरिका पहले ही आतंकवादी घोषित कर चुका है। साथ ही, रिपोर्ट में संभल में अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के तेजी से फैलने के बारे में भी बातें कही गई हैं।

जल संरक्षण के प्रति किया जागरूक

जौनपुर। भूजल सप्ताह्ष के अंतर्गत चलाए जा रहे सात दिवसीय जल संरक्षण एवं जन-जागरूकता अभियान के तहत बुधवार को पुलिस लाइन, जौनपुर में जल संरक्षण शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी लाइन्स गोल्डी गुप्ता ने पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जल संरक्षण, भूजल संवर्धन, जल के विवेकपूर्ण उपयोग तथा जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन की शपथ दिलाई।कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी पुलिसकर्मियों ने जल बचाने, भूजल स्तर को सुरक्षित रखने तथा आमजन को भी जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर प्रतिसार निरीक्षक सहित पुलिस लाइन के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन ने अपील की कि जल संरक्षण केवल सरकारी अभियान नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच का दायरा बढ़ा, कई जिलों में होगी संपत्तियों की पड़ताल

आर्यावर्त संवाददाता

अयोध्या। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब इसकी आंच लखनऊ तक पहुंच गई है। जांच एजेंसियां आरोपियों और उनके परिवार के 54 सदस्यों की संपत्तियों का ब्योरा जुटाने में लगी हैं। लखनऊ नगर निगम, लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA), आवास विकास परिषद, स्टाम्प विभाग और राजस्व विभाग से पिछले 2 सालों में खरीदी गई जमीन, मकान, फ्लैट, दुकान और अन्य संपत्तियों का रिकॉर्ड मांगा गया है। जानकारी के मुताबिक गोंडा, बस्ती, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और लखनऊ समेत कई जिलों में आरोपियों की संपत्तियों की पड़ताल की जा रही है। अयोध्या पुलिस ने जिलों के डीएम से जमीन और संपत्तियों के दस्तावेज मांगे हैं। आरोपियों और उनके परिवार के 54 सदस्यों की संपत्तियां जांच के दायरे में हैं। अधिकारियों से शहरी क्षेत्रों की संपत्तियों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में खरीदी गई कृषि भूमि की भी पूरी जानकारी मांगी है।

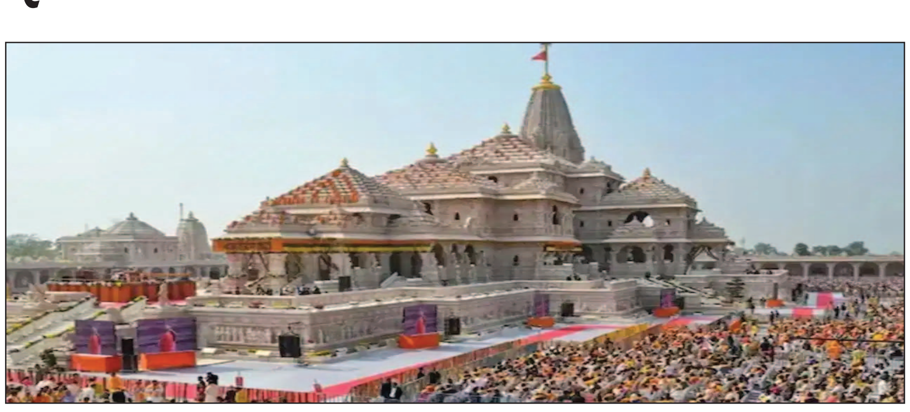

मकान, प्लॉट और दुकानों की जांच

जानकारी के मुताबिक संपत्तियों की जांच को लेकर अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रदीप वर्मा की तरफ से जो पत्र जारी किया गया है उसके तहत मकान, प्लॉट और दुकानों के अलावा कृषि वाली जमीनों की जांच की जा रही है। इसके लिए जिले के सभी उपजिलाधिकारियों और सहायक महानिरीक्षक स्टाम्प प्रथम व द्वितीय को भी पत्र भेज गया है।

रिकॉर्ड जुटाने की प्रक्रिया शुरू

यह जांच अयोध्या के SSP के पत्र के आधार पर शहर में कराई जा रही है। पत्र मिलने के बाद लखनऊ प्रशासन ने विभिन्न विभागों को सक्रिय करते हुए रिकॉर्ड जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी विभागों से प्राप्त जानकारी को एकत्र कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे आगे की जांच के लिए संबंधित एजेंसियों को भेजा जाएगा।

बेनामी संपत्तियां खरीदने का शक

अयोध्या पुलिस को शक है कि चढ़ावे की चोरी से मिली रकम से आरोपितों ने लखनऊ में बेनामी संपत्तियां खरीदी हों। अधिकारियों का कहना है कि संपत्तियों का ब्योरा मिलते ही उसकी वैधता की भी जांच की जाएगी। फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर तीनों विभागों से रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

किसानों की बदहाली और स्मार्ट मीटर के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। खरीफ की फसल की बुवाई और रोपाई के महत्वपूर्ण समय में किसानों को डीएपी खाद की उपलब्धता, स्मार्ट मीटर की मनमानी तथा बढ़ते बिजली बिलों के विरोध में बुधवार को जिला व शहर कांग्रेस कमेटी तत्वाधान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए और जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपकर जन समस्याओं के समाधान की मांग की है। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा एवं शहर कांग्रेस अध्यक्ष शकील अंसारी ने किया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि प्रदेश भर में किसान डीएपी खाद के लिए समितियों पर लंबी-लंबी कतारों में खड़े होने को मजबूर हैं, लेकिन खाद उपलब्ध नहीं हो रही है, वहीं स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद आम उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे जनता आर्थिक रूप से परेशान है।

ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस ने किसानों को तत्काल पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने तथा स्मार्ट मीटर हटाकर पुराने मीटर पुनः लगाने की मांग की, साथ ही चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र जनहित में निर्णय नहीं लिया तो कांग्रेस पार्टी व्यापक जनआंदोलन शुरू करेगी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों और आम जनता दोनों के साथ अन्याय कर रही है। धान की रोपाई के समय किसान खाद के लिए भटक रहे हैं, जबकि स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता की जेब काटी जा रही है। कांग्रेस पार्टी इस जनविरोधी नीति को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। यदि सरकार ने तत्काल खाद की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की और स्मार्ट मीटर की लूट बंद नहीं की, तो कांग्रेस सड़क से सदन तक बड़ा जनआंदोलन करेगी। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता हौसिला भीम, सुब्रत सिंह सैनी, राजेश तिवारी, ओमप्रकाश सिंह, अतहर नवाब, प्रेमप्रकाश, हाजी फिरोज अहमद, मानस तिवारी, ओमप्रकाश दुबे, शाहबाज खान,अर्श खान लकी, ममनून आलम, मोहसिन सलीम, उस्मान खा,विजयपाल, राजदेव पाल विभु पांडे, नंदलाल मौर्य, सुरेशचंद मिश्र, अनिल सिंह, अजय मिश्रा, सौरभ सिंह,विनोद पांडे, आवेश अहमद, रामशरण गौतम,सोहेल अहमद, देवेंद्र श्रीवास्तव, श्याम लगन कोरी, इन्द्रकेश शर्मा,बिलाल अहमद, विवेक सिंह, देवेंद्र कुमार पांडे, हाजी इरफान अहमद, युवराज यादव, इमरान अहमद, दिनेश तिवारी आदि लोग कार्यक्रम में शामिल रहे।

बच्चों में पानी की कमी को भूलकर भी न करें नजरअंदाज, बिगड़ सकती है सेहत

बच्चों के शरीर में पानी की कमी कई स्वास्थ्य समस्याओं की वजह बन सकती है। इसलिए इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसे में इसके कारण, लक्षण और बचाव के आसान तरीके जानना जरूरी है। आइए समझते हैं।

बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और सही विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। पानी शरीर का तापमान संतुलित रखने, पोषक तत्वों को शरीर के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचाने और शरीर से बेकार पदार्थ बाहर निकालने में मदद करता है। छोटे बच्चों के शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए उनमें पानी की कमी होने का खतरा भी जल्दी बढ़ सकता है। खासकर गर्म मौसम, तेज बुखार, उल्टी, दस्त या पर्याप्त तरल चीजें मिलने की वजह से बच्चे डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी का शिकार हो सकते हैं।

अगर समय रहते समस्या पर ध्यान न दिया जाए, तो बच्चे की तबीयत और बिगड़ सकती है। पानी की कमी की वजह से बच्चे में कमजोरी, सुस्ती, चक्कर आना, मुंह सूखना और कम पेशाब आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। गंभीर मामलों में डिहाइड्रेशन की वजह से बच्चे को अस्पताल में इलाज की जरूरत भी पड़ सकती है। इसलिए माता-पिता के लिए यह जानना जरूरी है कि बच्चों में पानी की कमी के लक्षण कैसे पहचानें और ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। आइए इस बारे में डिटेल में जानते हैं।

बच्चों में पानी की कमी के क्या लक्षण दिखते हैं?

अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (AAP) की आधिकारिक वेबसाइट HealthyChildren ।org के अनुसार, बच्चों में पानी की कमी होने पर कई तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। बच्चे को सामान्य से ज्यादा प्यास लग सकती है और उसका मुंह व होंठ सूखे हुए महसूस हो सकते हैं। पेशाब कम आना या गहरे पीले रंग का पेशाब भी डिहाइड्रेशन का संकेत हो सकता है।

छोटे बच्चों में रोते समय आंसू कम आना, आंखें धंसी हुई दिखना और सिर का मुलायम हिस्सा धंसा हुआ नजर आना भी पानी की कमी का संकेत हो सकता है। बच्चा सुस्त दिखाई दे सकता है, खेलने में रुचि कम दिखा सकता है या जरूरत से ज्यादा नींद आ सकती है। अगर बच्चे में ये लक्षण दिखाई दें, तो इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और समय रहते जरूरी कदम उठाने चाहिए।

बच्चों में पानी की कमी होने पर क्या करें?

अगर बच्चे में पानी की कमी के हल्के लक्षण दिखाई दें, तो उसे थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बार-बार पानी या ORS घोल पिलाएं। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग जारी रखें। बड़े बच्चों को पानी के साथ अन्य तरल चीजें भी दी जा सकती हैं, अगर डॉक्टर ने मना न किया हो।

बच्चे को एक साथ बहुत ज्यादा तरल चीजें देने की बजाय थोड़ी-थोड़ी मात्रा में देना बेहतर होता है। अगर बच्चे की हालत में सुधार न हो या लक्षण बढ़ने लगें, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

कब तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?

अगर बच्चा बहुत सुस्त हो जाए, बार-बार उल्टी कर रहा हो, पानी या ORS भी न पी पा रहा हो, पेशाब बहुत कम आ रहा हो या कई घंटों तक पेशाब न आए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

इसके अलावा, अगर डिहाइड्रेशन के लक्षण तेजी से बढ़ रहे हों या बच्चे की हालत लगातार बिगड़ रही हो, तो बिना देर किए मेडिकल मदद लेना जरूरी है। समय पर इलाज मिलने से गंभीर समस्याओं का खतरा कम किया जा सकता है।

बिना मशीन घर पर बनाएं 5 कैफे स्टाइल कॉफी, हर कोई करेगा तारीफ

कैफे जैसी कॉफी पीने के लिए हर बार बाहर जाना जरूरी नहीं है। बिना किसी महंगी मशीन के भी घर पर स्वादिष्ट और झागदार कॉफी बनाई जा सकती है। आइए जानते हैं 5 आसान कैफे स्टाइल कॉफी रेसिपीज़।

कॉफी कई लोगों की पसंदीदा ड्रिंक है। सुबह की ताजगी से लेकर शाम की हल्की थकान दूर करने तक, कई लोग अपने दिन की शुरुआत या ब्रेक के समय एक कप कॉफी पीना पसंद करते हैं। आमतौर पर लोग कैफे में मिलने वाली झागदार और स्वादिष्ट कॉफी का आनंद लेते हैं, लेकिन हर बार बाहर जाकर कॉफी पीना संभव नहीं होता। ऐसे में बिना किसी महंगी मशीन के भी घर पर कैफे जैसा स्वाद तैयार किया जा सकता है।

कॉफी में कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। सीमित मात्रा में कॉफी पीना एनर्जी महसूस कराने में मदद कर सकता है। हालांकि, जरूरत से ज्यादा कॉफी पीने से नींद में परेशानी, घबराहट या बेचैनी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इसका सेवन हमेशा संतुलित मात्रा में करना चाहिए। अगर आप भी घर पर बिना मशीन के कैफे जैसा स्वाद पाना चाहते हैं, तो कुछ आसान रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि बिना मशीन घर पर कौन-सी कैफे स्टाइल कॉफी बनाई जा सकती हैं।

बिना मशीन घर पर बनाएं ये 5 कैफे स्टाइल कॉफी

फेंटी हुई कॉफी (डालगोना कॉफी)

एक बाउल में कॉफी, चीनी और थोड़ा गर्म पानी डालकर अच्छी तरह फेंटें, जब तक गाढ़ा झाग न बन जाए। अब एक गिलास में ठंडा दूध और बर्फ डालें, ऊपर से तैयार झाग रखें। यह कॉफी दिखने में आकर्षक और स्वाद में क्रीमी व हल्की मीठी होती है।

कोल्ड कॉफी

मिक्सर में ठंडा दूध, कॉफी, चीनी और बर्फ के टुकड़े डालकर अच्छी तरह ब्लेंड करें। चाहें तो ऊपर से थोड़ी व्हिप्ड क्रीम या चॉकलेट पाउडर डाल सकते हैं। यह कॉफी गर्मियों में ठंडक देने वाली और कैफे जैसी स्मूद व रिफ्रेशिंग लगती है।

हॉट कैपुचिनो स्टाइल कॉफी

एक कप में कॉफी, चीनी और थोड़ा गर्म पानी डालकर अच्छी तरह फेंट लें। अलग से दूध गर्म करके उसे थोड़ा झागदार करें और कॉफी वाले मिश्रण में डाल दें। ऊपर से थोड़ा कोको पाउडर छिड़कें। इसका स्वाद हल्का, झागदार और कैफे जैसा क्रीमी होता है।

वनीला कॉफी

गर्म या ठंडे दूध में कॉफी और चीनी मिलाएं। इसमें कुछ बूंदें वनीला एसेंस डालकर अच्छी तरह मिला लें। चाहें तो ऊपर से झाग या क्रीम भी डाल सकते हैं। वनीला की हल्की खुशबू इस कॉफी को कैफे जैसा खास स्वाद देती है।

चॉकलेट मोका कॉफी

गर्म दूध में कॉफी, थोड़ा कोको पाउडर और चीनी मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें। ऊपर से चॉकलेट के छोटे-छोटे टुकड़े या कोको पाउडर डालकर परोसें। कॉफी और चॉकलेट का मेल इसे गाढ़ा, खुशबूदार और बेहद स्वादिष्ट बनाता है।

कैफे स्टाइल कॉफी बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान

कैफे स्टाइल कॉफी बनाते समय अच्छी क्वॉलिटी वाली कॉफी का इस्तेमाल करें। कॉफी, दूध और चीनी की मात्रा अपने स्वाद के अनुसार संतुलित रखें। अगर झागदार कॉफी बनानी है, तो कॉफी और चीनी को गर्म पानी के साथ अच्छी तरह फेंटें। ठंडी कॉफी बनाते समय ठंडा दूध और बर्फ का इस्तेमाल करें, जबकि हॉट कॉफी के लिए ताजा गर्म दूध लें।

ज्यादा चीनी या सिरप डालने से स्वाद जरूरत से ज्यादा मीठा हो सकता है। चाहें तो ऊपर से थोड़ा कोको पाउडर, दालचीनी पाउडर या चॉकलेट के छोटे-छोटे टुकड़े डालकर कॉफी को और भी आकर्षक बना सकते हैं।

क्या कैंसर के खतरे को सच में कम करता है लहसुन, डॉक्टर से जानें ये मिथ या सच

कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को बहुत देर से पता चलता है। इससे बचने के लिए कई घरेलू नुस्खे आजमाए जाते हैं। कहते हैं कि रोजाना एक लहसुन की कली खाई जाए तो कैंसर का खतरा कम हो जाता है। पर क्या ऐसा सच में होता है?

रोजाना लहसुन की एक कली खाई जाए और कैंसर से बचाव? क्या ऐसा सच में संभव है? भारत में कैंसर के इलाज या बचाव के लिए ऐसे कई घरेलू उपाय लोग अपनाते हैं। पर ये कितने कारगर हैं इसको लेकर अभी भी कई रिसर्च होने बाकी हैं। लहसुन हमें कैंसर से बचाने में काम आता है।। ये मिथक है या सच।। इसका पता लगाए बिना कुछ लोग इसे रोजाना खाने लगते हैं। लहसुन में कई तत्व और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं लेकिन ये कैंसर का इलाज है... ऐसा मानना गलत है।

लहसुन हमें कई बीमारियों और हेल्थ प्रॉब्लम्स से बचा सकता है। पर ये कैंसर के खिलाफ पूरी तरह कारगर साबित हो ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए आपको एक्सपर्ट के जरिए बताते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है।

एक्सपर्ट ने क्या कहा?

डॉ. मनीष साहनी (कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कैलाश दीपक हॉस्पिटल) का कहना है कि अगर लहसुन की बात करें, तो इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। इसमें विटामिन बी, विटामिन सी जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ सल्फर यौगिक, जैसे एलिसिन और एस एल एल सिस्टीन, मौजूद होते हैं, जिनमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीमाइक्रोबियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। ये गुण हमारे शरीर और समग्र स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माने जाते हैं।

अब अगर इस सवाल की बात करें कि क्या लहसुन कैंसर के खतरे को कम करता है, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह धारणा कि लहसुन कैंसर का इलाज कर सकता है, एक मिथक है। अब तक किसी भी मानव अध्ययन में यह साबित नहीं हुआ है कि लहसुन कैंसर को ठीक कर सकता है या यह अपने आप में कैंसर रोधी उपचार है।

एक्सपर्ट ने कहा, कुछ अध्ययनों में यह देखा गया है कि यदि सप्ताह में लगभग 5 से 10 ग्राम या उससे अधिक मात्रा में लहसुन का सेवन किया जाए, तो पेट के कैंसर और कुछ कोलोरेक्टल कैंसर के जोखिम में मामूली कमी देखी गई है।

लहसुन के दूसरे फायदे

लहसुन में एलिसिन, फ्लेवोनॉयड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसमें मौजूद एलिसिन से हमारी इम्यूनिटी को फायदा होता है क्योंकि ये बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के खिलाफ काम करता है। इसलिए माना जाता है कि लहसुन के सेवन से सर्दी-जुकाम से बचा जा सकता है।

ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी लहसुन काम आता है। दरअसल, इस सफेद चीज की मदद से हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ पाता है। इस तरह ब्लड वेसेल्स रिलैक्स होती हैं। इस तरह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है।

कई शोध के मुताबिक ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कुछ हद तक कम करता है। इसके अलावा ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी घटा सकता है। इसमें कई एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसलिए ये फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से भी बचाने में कारगर साबित हो सकता है।

क्या है एफसीएनआर डिपॉजिट? रुपए को कैसे बूस्ट करता है एनआरआई का ये पैसा

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई एफसीएनआर(B) स्वैप विंडो के जरिए भारत में रिकॉर्ड डॉलर आ रहे हैं। जानिए एफसीएनआर डिपॉजिट का पूरा गणित और रुपए को मजबूती देने में इसका रोल क्या है?

जब भी ग्लोबल इकोनॉमी में उथल-पुथल होती है या अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया गिरना शुरू होता है, तब बैंकिंग और इकोनॉमी के गलियारों में 'एफसीएनआर Deposits' का जिक्र तेजी से होने लगता है। हाल ही में रिजर्व बैंक की विशेष 'स्वैप विंडो' के तहत भारतीय बैंकों में एफसीएनआर डिपॉजिट्स के जरिए अरबों डॉलर का भारी-भरकम इनफ्लो देखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार मात्र 42 दिनों में एफसीएनआरबी के जरिए 21 अरब डॉलर से ज्यादा चुके हैं। जानकारों का अनुमान है कि ये आंकड़ा 50 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर सकता है। लेकिन आम आदमी और निवेशकों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि FCNR अकाउंट क्या होता है और गैर-रिहायशी भारतीयों (NRIs) का यह पैसा भारतीय करेंसी को कैसे सहारा देता है? आइए आसान भाषा में समझते हैं।

एफसीएनआर डिपॉजिट आखिर क्या है?

एफसीएनआर का पूरा नाम Foreign Currency Non-Resident (Bank) Deposit यानी 'विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक जमा' होता है। यह NRIs (Non-Resident Indians) और PIOs (Persons of Indian Origin) के लिए भारत के बैंकों में खोला जाने वाला एक विशेष फिक्स्ड डिपॉजिट (Term Deposit) अकाउंट है। सबसे मुख्य बात ये है कि सामान्य NRE या NRO अकाउंट्स में NRI जो पैसा भेजते हैं, वह बैंक में आते ही भारतीय रुपए में बदल जाता है। लेकिन FCNR अकाउंट में पैसा विदेशी मुद्रा (जैसे अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, जापानी येन आदि) में ही जमा रहता है और ब्याज भी उसी करेंसी में मिलता है।

एफसीएनआर अकाउंट्स की क्या है प्रमुख खासियत

करेंसी रिस्क से पूरी आजादी

FCNR डिपॉजिट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें जमाकर्ता को एक्सचेंज रेट के उतार-चढ़ाव का कोई खतरा नहीं होता। अगर किसी NRI ने 10,000 डॉलर जमा किए हैं, तो मैच्योरिटी पर उन्हें ब्याज सहित पूरा पैसा डॉलर में ही वापस मिलेगा—चाहे उस दौरान रुपया कितना भी मजबूत या कमजोर क्यों न हुआ हो।

भारत में पूरी तरह टैक्स-फ्री

एफसीएनआर अकाउंट में डिपॉजिट प्रिंसीपल और उस पर मिलने वाले ब्याज पर भारत में कोई इनकम टैक्स या दूसरा टैक्स नहीं देना पड़ता।

पूरी तरह ट्रांसफेरेबल

मैच्योरिटी पूरी होने पर जमाकर्ता बिना किसी कागजी जटिलता या सरकारी अनुमति के अपना पूरा पैसा और ब्याज वापस विदेश ले जा सकता है।

अब तक कितना आ गया पैसा?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नॉन-रेसिडेंट भारतीयों (NRIs) से फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट को बढ़ावा देने के लिए खास उपाय किए हैं। इन उपायों की वजह से पिछले शुक्रवार तक फॉरेन करेंसी नॉन-रेसिडेंट (FCNR(B)) डिपॉजिट के तौर पर 17।4 अरब डॉलर आए हैं, जो इस स्कीम में निवेशकों की गहरी दिलचस्पी को दिखाता है। RBI ने एक बयान में कहा कि कंपनियों ने एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग (ECB) के जरिए 1।34 अरब डॉलर जुटाए, जबकि ओवरसीज फॉरेन करेंसी बॉरोइंग (OFCB) से 1.97 अरब डॉलर और आए।

स्पेशल एफसीएनआर(B) डिपॉजिट विंडो समेत ये उपाय, सेंट्रल बैंक की फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करने और रुपए को सपोर्ट करने की बड़ी कोशिशों का हिस्सा हैं, जो क्रूड ऑयल की बढ़ी हुई कीमतों के दबाव के बीच रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब बना हुआ है। RBI ने ऑथराइज्ड डीलर बैंकों से मिले सबमिशन के आधार पर लेटेस्ट फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो डेटा जारी किया।

फ्रेश एफसीएनआर(B) डिपॉजिट के लिए स्पेशल फैसिलिटी 30 सितंबर तक खुली रहेगी, जबकि ECBs और OFCBs के लिए विंडो 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। RBI की स्वैप विंडो एलिजिबल बैंकों और बॉरोअर्स को सेंट्रल बैंक के साथ कंसेशनल रेट पर एलिजिबल फॉरेन करेंसी इनफ्लो एक्सचेंज करने की इजाज़त देती है। इससे हेजिंग कॉस्ट कम होती है और विदेशों से फंड जुटाना ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है।

रुपए को कैसे मजबूती देता है NRI का यह पैसा?

जब भी विदेशी बाजारों में डॉलर की मांग बढ़ती है या विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकालते हैं, तो भारत में डॉलर की कमी होने लगती है और रुपया कमजोर होने लगता है। ऐसे समय में FCNR डिपॉजिट्स भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 'सुरक्षा कवच' का काम करते हैं...

1- देश में डॉलर की लिक्विडिटी (सप्लाई) बढ़ाना : जब NRIs एफसीएनआर अकाउंट्स में बड़ी रकम जमा करते हैं, तो भारतीय बैंकिंग सिस्टम में सीधे फॉरेन करेंसी का प्रवेश होता है। बाजार में डॉलर की उपलब्धता बढ़ने से रुपए की मांग और सप्लाई का संतुलन बनता है।

2- फॉरेक्स रिजर्व को बूस्ट : बैंक एफसीएनआर अकाउंट्स में आए डॉलर को रिजर्व बैंक में जमा करा सकते हैं या अंतरराष्ट्रीय व्यापार वित्तपोषण (Trade Finance) के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भारत का फॉरेक्स रिजर्व मजबूत होता है, जो देश की रेटिंग और आर्थिक साख के लिए बेहद जरूरी है।

3- RBI की 'स्वैप विंडो' का जादू : जब रिजर्व बैंक को लगता है कि बाजार में डॉलर की किल्लत है, तो वह बैंकों के लिए एक विदेशी मुद्रा स्वैप विंडो खोलता है। बैंक NRIs से जुटाए गए FCNR डॉलर को निश्चित अवधि के लिए RBI को सौंप देते हैं। बदले में RBI बैंकों को रुपये दे देता है ताकि वे घरेलू बाजार में कर्ज दे सकें। अवधि पूरी होने पर RBI बैंकों को वापस डॉलर लौटा देता है। जिससे RBI को बाजार से महंगे डॉलर खरीदे बिना ही फॉरेक्स रिजर्व में तुरंत अरबों डॉलर मिल जाते हैं।

4- रुपए की गिरावट पर लगाम : जब विदेशी बाजारों में रुपए पर दबाव होता है, तो FCNR डिपॉजिट्स के जरिए आया डॉलर का इनफ्लो बाजार में एक बफर की तरह काम करता है, जिससे रुपया अचानक धड़ाम से गिरने से बच जाता है। FCNR डिपॉजिट्स भारत सरकार और रिजर्व बैंक के पास एक ऐसा असरदार आर्थिक हथियार हैं, जो एक तरफ NRIs को उनके विदेशी फंड पर सुरक्षित और टैक्स-फ्री रिटर्न देता है, तो दूसरी तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट के समय डॉलर का बैकअप देकर रुपये की साख को बनाए रखता है।

एक्वाकल्चर और तंबाकू किसानों के साथ खड़ी सरकार : उचित दाम और निर्यात बढ़ाने का वादा, बोले पीयूष गोयल

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक्वाकल्चर क्षेत्र को मजबूत करने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि इससे भारत की तटीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, किसानों की आजीविका बेहतर होगी और निर्यात वृद्धि के नए अवसर पैदा होंगे।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में गोयल ने बताया कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के एक्वाकल्चर और तंबाकू उद्योग से जुड़े पक्षकारों के साथ सार्थक बातचीत की।

गोयल ने कहा, 'हमने भारत की तटीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए एक्वाकल्चर क्षेत्र को और सशक्त बनाने के अवसरों पर चर्चा की।' उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को उचित मूल्य, बेहतर बाजार पहुंच और निर्यात बढ़ाने के नए अवसर उपलब्ध कराकर उनकी आजीविका को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन प्रयासों से आंध्र प्रदेश की आर्थिक प्रगति को भी गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि एक्वाकल्चर राज्य के प्रमुख निर्यात केंद्रित क्षेत्रों में से एक है और भारत के सीफूड निर्यात में इसका महत्वपूर्ण योगदान है।

बैठक में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू किंजारापु, भारी उद्योग एवं इस्पात राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा, भाजपा नेता डी. पुरंदेश्वरी, टीडीपी संसदीय दल के नेता लावू श्रीकृष्ण देवरायालु तथा आंध्र प्रदेश के मंत्री के. अच्चन्नायडू, गोट्टीपाटी रवि कुमार और डोला बाला वीरंजनय स्वामी भी शामिल हुए।

यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसी दिन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने राज्य के एक्वाकल्चर और तंबाकू किसानों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार से कई कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बढ़ती उत्पादन लागत और वैश्विक बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच किसानों को राहत देने की जरूरत है।

मुख्यमंत्री ने गोयल समेत केंद्रीय मंत्रियों को अलग-अलग पत्र लिखकर झींगा चारा बनाने वाली इकाइयों के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) सोयाबीन मील के आयात की अनुमति देने, घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए फिश मील के निर्यात को विनियमित करने, तंबाकू निर्यात पर प्रोत्साहन देने, एक्वाकल्चर से जुड़े प्रमुख इनपुट पर जीएसटी कम करने और अमरावती में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की मांग की।

पीयूष गोयल को लिखे अपने पत्र में चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि फिश मील के निर्यात को इस तरह नियंत्रित किया जाए कि पहले घरेलू मांग पूरी हो, उसके बाद ही विदेशों में निर्यात की अनुमति दी जाए। उन्होंने जीएम सोयाबीन मील के आयात की अनुमति देने की मांग भी दोहराई और कहा कि इससे कमी दूर होगी तथा झींगा पालकों के लिए चारे की लागत कम करने में मदद मिलेगी।

आसियान की भूमिका पर QUAD की मुहर, हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए बना ये प्लान

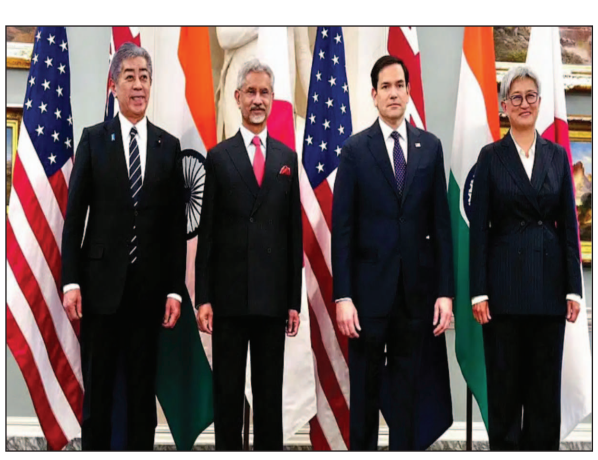

फिलीपींस एजेंसी। फिलीपींस की राजधानी मनीला में बुधवार (22 जुलाई) को क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया) के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इस दौरान हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और नियम-आधारित व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में चारों देशों ने आसियान (ASEAN) की एकता और उसकी केंद्रीय भूमिका के प्रति अपने अटूट समर्थन को दोहराया।

भारत के विदेश मंत्री डॉ। एस। जयशंकर, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने कहा कि चारों देश आसियान के व्यापक रणनीतिक साझेदार (Comprehensive Strategic Partners) होने के नाते क्षेत्र की स्थिरता और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा

क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र के सामने मौजूद चुनौतियों और अवसरों पर विस्तार से चर्चा हुई। विदेश मंत्रियों ने आसियान आउटलुक ऑन द इंडो-पैसिफिक (AOIP) के व्यावहारिक क्रियान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। इसके तहत समुद्री और अंतरराष्ट्रीय अपराधों से जुड़ी सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया गया।

सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति

संयुक्त बयान में कहा गया कि हिंद-प्रशांत के समुद्री क्षेत्र में शांति और स्थिरता पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि की आधारशिला है। इसी सोच के साथ क्वाड देश क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करने तथा आसियान के साथ मिलकर व्यावहारिक पहल को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चारों देशों के बीच मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी।

यह बैठक ऐसे समय हुई है जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखलाओं की मजबूती, उभरती तकनीकों और क्षेत्रीय भू-राजनीतिक चुनौतियों को लेकर सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। क्वाड देशों ने संकेत दिया कि इन साझा प्राथमिकताओं पर आसियान के साथ समन्वय भविष्य में और गहरा किया जाएगा।

मध्यस्थता कराने वाले पाकिस्तान ने अमेरिका से मांगे पैसे, 10 अरब डॉलर के मदद की लगाई गुहार

वॉशिंगटन, एजेंसी। गंभीर आर्थिक संकट और विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी से जूझ रहे पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने एक बड़ा और चौंकाने वाला प्रस्ताव रखा है। ईरान और अमेरिका के बीच हालिया तनाव और संघर्ष के दौरान कथित तौर पर मध्यस्थता यानी 'ब्रोकरेज' की भूमिका निभाने के बाद, अब पाकिस्तान ने ट्रंप प्रशासन से 10 अरब डॉलर की भारी-भरकम वित्तीय सहायता की मांग की है।

यह मांग 'बायलैटरल एक्सचेंज स्टेबिलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी' के तहत की गई है। पाकिस्तान का मानना है कि अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो उसकी गंभीर आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान ने यह अनुरोध अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के सामने रखा है। हालांकि, अब तक अमेरिका की ओर से इस प्रस्ताव पर कोई आधिकारिक मंजूरी या सकारात्मक संकेत नहीं मिला है।

अमेरिका-ईरान तनाव के बीच पाकिस्तान की सक्रियता

हाल के महीनों में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़े तनाव के दौरान पाकिस्तान ने खुद को एक संभावित मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश की। पाकिस्तान को उम्मीद है कि इस भूमिका के बदले उसे अमेरिका और अन्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से आर्थिक सहयोग मिल सकता है। यह व्यवस्था पांच साल तक के लिए प्रस्तावित की गई है।

है 'बायलैटरल एक्सचेंज स्टेबिलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी'?

यह एक ऐसी वित्तीय व्यवस्था है जिसके तहत अमेरिका किसी सहयोगी देश के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए डॉलर, मुद्रा स्वैप या वित्तीय गारंटी जैसी सहायता उपलब्ध कराता है। यदि पाकिस्तान को यह सुविधा मिलती है, तो उसके लिए बड़ी राहत होगी।

विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हो सकती है।

पाकिस्तानी रुपये पर दबाव कम हो सकता है।

आयात भुगतान और बाहरी कर्ज चुकाने में आसानी हो सकती है।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों पर निर्भरता कुछ हद तक घट सकती है।

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था क्यों संकट में है?

पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। देश अभी भी IMF के 7 अरब डॉलर के बेलआउट कार्यक्रम के तहत आर्थिक सुधार लागू कर रहा है। इस कार्यक्रम की शर्तों के तहत सरकार को टैक्स बढ़ाने, सब्सिडी कम करने और सरकारी खर्च में कटौती जैसे कई कठिन फैसले लेने पड़े हैं। इन कदमों का सीधा असर आम जनता पर पड़ा है। महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती जीवन-यापन लागत को लेकर सरकार की आलोचना लगातार बढ़ रही है।

IMF और विश्व बैंक से भी उम्मीदें

पाकिस्तान को उम्मीद है कि अगप अमेरिका का समर्थन मिलता है तो विश्व बैंक, IMF और अन्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से भी अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्राप्त करने में उसे आसानी होगी। इससे देश की वित्तीय स्थिति को कुछ राहत मिल सकती है।

क्या अमेरिका देगा मदद?

फिलहाल अमेरिका की ओर से पाकिस्तान की इस मांग पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप प्रशासन इस प्रस्ताव पर विचार करेगा या नहीं।यदि अमेरिका इस तरह की सहायता को मंजूरी देता है, तो इससे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को अल्पकालिक राहत मिल सकती है। वहीं अगर यह प्रस्ताव खारिज होता है, तो पाकिस्तान को अपनी आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए IMF और अन्य वैश्विक संस्थानों पर ही अधिक निर्भर रहना पड़ सकता है।

पहले 0 फिर 100 और फिर 200%... ट्रंप की नई जेनेरिक दवा टैरिफ स्कीम भारत पर कैसे डाल सकती है असर

वॉशिंगटन, एजेंसी। "यूएस-ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने मंगलवार को इंपोर्ट की जाने वाली जेनेरिक दवाओं पर चरणबद्ध तरीके से टैरिफ (आयात शुल्क) लगाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये दवाएं दो साल तक अमेरिका में बिना किसी शुल्क (ड्यूटी-फ्री) के आती रहेंगी और उसके बाद भारी टैरिफ बढ़ाया जाएगा ताकि दवा बनाने का काम (मैन्युफैक्चरिंग) वापस देश में लाया जा सके।

'2028 के बाद लगेगा 200 प्रतिशत टैरिफ'

उन्होंने कहा कि इस कदम का मकसद ऐसी फार्मास्युटिकल दवाओं का उत्पादन देश के भीतर ही शुरू करना है। उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा, '1 अगस्त, 2026 से अमेरिका में आने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर दो साल तक जीरो परसेंट टैरिफ लागू रहेगा। इसके बाद एक साल के लिए टैरिफ बढ़ाकर 100% कर दिया जाएगा और उसके बाद इसे 200% कर दिया जाएगा।'

'अमेरिकियों की सुरक्षा करना है मकसद'

इस पॉलिसी की घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा कि इस कदम का मकसद कंपनियों को देश के अंदर ही जेनेरिक दवाएं बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा, 'ऐसा जेनेरिक दवा बनाने का काम अमेरिका में वापस लाने के लिए किया जा रहा है। जो कंपनियां तय समय सीमा के अंदर प्लांट और उपकरण नहीं लगाएंगी उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस पॉलिसी का मकसद अमेरिकी लोगों की सुरक्षा करना है।'

उन्होंने कहा, 'पेटेंट वाली, ब्रांडेड या नई (इनोवेटिव) दवाओं' के लिए पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि वह सफल रही है। ट्रंप ने यह भी कहा कि पूरे अमेरिका में दवा बनाने की सुविधाएं पहले कभी न देखे गए स्तर पर बनाई जा रही हैं।

पिछले साल बड़ी दवा कंपनियों ने अमेरिकी सरकार के साथ समझौते किए जिनके तहत अरबों डॉलर की दवाओं को टैरिफ से छूट दी गई। वहीं ट्रंप ने इम्पोर्ट की जाने वाली ब्रांडेड दवाओं पर भी टैरिफ लगाया जब तक कि बनाने वाली कंपनियां कीमत से जुड़े समझौतों के लिए तैयार न हों या उन्हें अमेरिका में ही बनाने का वादा न करें।

भारत पर कितना असर?

जैसा कि ट्रंप ने कहा कि टैरिफ का यह चरण-दर-चरण ढांचा खास तौर पर अंतरराष्ट्रीय दवा निर्माताओं को एक अल्टीमेटम देने के लिए बनाया गया है ताकि वे अमेरिका के घरेलू इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करें वरना उन्हें भारी आर्थिक जुर्माना भरना पड़ सकता है।

यह बढ़ोतरी विदेशी एक्सपोर्ट हब खासकर भारत के लिए लंबे समय की एक बड़ी चुनौती है। गौरतलब है कि भारतीय दवा निर्माता अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली कुल जेनेरिक दवाओं का लगभग 40% हिस्सा सप्लाई करते हैं। भारत को अक्सर दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है क्योंकि यहां यूएस एफडीए से मंजूरी प्राप्त 3,000 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं।

इस बात को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजित USISPF इंडिया लीडरशिप समिट में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा, 'भारतीय फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री का योगदान इस बात से साबित होता है कि अमेरिका के बाहर सबसे ज्यादा यूएस एफडीए-अप्रूव्ड फार्मास्युटिकल प्लांट भारत में ही हैं। यह अमेरिका के बाहर मौजूद कुल US FDA-अप्रूव्ड प्लांट का 25 प्रतिशत है।'

उन्होंने कहा कि भारतीय जेनेरिक दवाओं ने 2022 में अमेरिकी हेल्थकेयर सिस्टम को 219 अरब डॉलर की बचत कराई और 2013 से 2022 के बीच कुल 1.3 ट्रिलियन डॉलर की बचत हुई।

सरकार चर्चा को तैयार, किरेन रिजिजू ने संसद में विपक्ष की मांग पर दिया बड़ा बयान

नई दिल्ली, एजेंसी। आज संसद के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है। उम्मीद है कि दोनों सदनों में विपक्ष फिर से विरोध-प्रदर्शन करेगा, क्योंकि वे NEET परीक्षा विवाद, दिल्ली में CJP प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, राम मंदिर दान के पैसे की चोरी और दूसरे मुद्दों पर तुरंत चर्चा की मांग कर रहे हैं। यह सत्र प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी के नेतृत्व में हुए अभूतपूर्व विरोध-प्रदर्शन के एक दिन बाद हो रहा है, जिससे संसद में एक और हंगामेदार दिन की संभावना बन गई है।

सरकार ने कहा है कि वह NEET विवाद पर चर्चा के लिए तैयार है और वंदे मातरम बिल समेत कई अहम बिल भी पेश कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने से पहले NCP (SP) प्रमुख शरद पवार और सांसद सुप्रिया सुले से मुलाकात की। यह मुलाकात विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के कई अन्य नेताओं को एक दिन पहले हिरासत में लिए जाने के विरोध में विपक्षी दलों के प्रदर्शनों के बीच हुई।

संसद में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी रहने की संभावना है, क्योंकि विपक्ष नियम 193 के तहत चर्चा के लिए सहमत नहीं है, जिसके तहत मतदान के बिना अल्पकालिक चर्चा का प्रावधान है। इसके बजाय, विपक्षी दल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि NEET विवाद और विरोध प्रदर्शनों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से उठाया जाए, जिसके तहत सदन की अन्य सभी कार्यवाही को स्थगित करके इस मामले पर चर्चा की जाए। विपक्ष ने अपना रुख लोकसभा अध्यक्ष को बता दिया है।

विपक्षी दलों ने संसद में मिलकर विरोध प्रदर्शन किया

विपक्षी दलों ने संसद में मिलकर विरोध प्रदर्शन किया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग की।

'समय बर्बाद न करें': सीजेपी प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई का मामला, तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार क्यों?

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के मार्च के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। वकील नरेंद्र मिश्रा ने चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का जिक्र करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की। इस पर सीजेआई ने कहा, हमारा समय बर्बाद मत कीजिए और अपना समय भी बर्बाद मत कीजिए।

हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं: सीजेआई

वकील ने कहा कि छात्र नीट परीक्षा सही तरीके से कराने और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार जैसे अहम मुद्दे उठा रहे हैं। इस पर

सीजेआई ने उनकी बात बीच में रोकते हुए कहा - 'बहुत-बहुत धन्यवाद।' जब वकील ने कहा कि पुलिस की ज्यादती दिखाने वाले वीडियो मौजूद हैं, तो सीजेआई ने कहा, हमें वीडियो में दिलचस्पी नहीं है। हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं है।

याचिका में क्या आग्रह किया गया?

याचिका में दावा किया गया था कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की ओर से आयोजित प्रदर्शन में पुलिस ने छात्रों पर बल प्रयोग किया। इसमें शीर्ष कोर्ट से तत्काल दखल देने का आग्रह किया गया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार किया। कोर्ट ने इस याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की मांग को स्वीकार नहीं किया। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इसी तरह के एक मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार किया था। हाईकोर्ट ने कहा था- कोर्ट को इसमें न घसीटें।

'टॉक्सिक' का दूसरा गाना 'मदहोश' रिलीज, यश और तारा की केमिस्ट्री के साथ दिखी इस अभिनेत्री की झलक

यश स्टारर अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' का नया गाना मंगलवार को रिलीज हुआ। गाने का टाइटल 'मदहोश' है और इसे आवाज दी है सिद्धार्थ बसरूर ने। वहीं गाने का म्यूजिक तनिष्क बागची, फहीम अब्दुल्ला और अरसलान निजामी ने दिया है। गीत लिखा है अरसलान निजामी और सैयद मुराद गिलानी ने।

मंगलवार को रिलीज हुए इस गाने के वीडियो में यश और अभिनेत्री तारा सुतारिया के बीच की जबरदस्त कैमिस्ट्री देखने को मिली। बता दें यह फिल्म का दूसरा गाना है। इससे पहले यश और कियारा का गाना तबाही रिलीज हुआ था।

गाने के वीडियो में क्या खास

3 मिनट 14 सेकंड के इस वीडियो सॉन्ग में राया बने यश और रिबेका बनीं तारा के बीच का कनेक्शन पेश किया गया है। प्रपोज करने से लेकर, प्यार और फिर तकरार होने तक का सफर दिखाया गया है। इसके अलावा गाने में कियारा आडवाणी और नयनतारा की भी झलक मिली है।

26 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म

यश, नयनतारा, कियारा, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत और हुमा कुरैशी जैसे कलाकारों से सजी यह फिल्म इस साल 26 अगस्त के दिन रिलीज होगी। फिल्म का निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है। यह कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा में शूट हुई है वहीं इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम समेत अन्य भाषाओं में डब किया गया है।

पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने के बाद महाकाल के दरबार पहुंचे कार्तिक आर्यन; दर्शन कर साझा की तस्वीर

अभिनेता कार्तिक आर्यन उज्जैन महाकाल के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर साझा की है।

अभिनेता कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी आगामी फिल्मों- 'नागजिला' और 'कैप्टन इंडिया' की तैयारियों में व्यस्त हैं। इस बीच बीते दिनों उनके नाम का एलान राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए किया गया। 18 जुलाई को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का एलान हुआ। कार्तिक ने फिल्म 'चंदू चैंपियन' के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड जीता है। इसके बाद वे महाकाल के दर्शन करने पहुंचें।

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने के बाद अभिनेता कार्तिक आर्यन उज्जैन पहुंचे और उन्होंने महाकाल के दर्शन किए। अभिनेता ने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक फोटो साझा किया है। वे मंदिर प्रांगण में भक्ति भाव में लीन होकर हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं। एक्टर ने फोटो के साथ कैप्शन लिखा है, 'जय महाकाल'। बता दें कि कार्तिक का यह पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है।

कार्तिक आर्यन के इस पोस्ट पर नेटिजंस कमेंट करते हुए एक्टर की तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, 'राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कार्तिक'। एक यूजर ने लिखा है, 'हमारा दिल आज बहुत खुश हो गया है'। एक यूजर ने लिखा, 'चैंपियन'। वहीं, कुछ यूजर्स उन्हें आगे बढ़ने और इसी तरह तरक्की करते रहने के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी के साथ नेटिजंस 'जय महाकाल' का जयकारा भी लिख रहे हैं।

फिल्म 'चंदू चैंपियन' के लिए किया था ट्रांसफॉर्मेशन

बता दें कि बीते दिनों 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं के नाम से पर्दा उठा। यह पुरस्कार साल 2024 में रिलीज हुई फिल्मों और परफॉर्मेंस के लिए प्रदान किए जाएंगे। 2024 में आई फिल्म 'चंदू चैंपियन' में एक्टर ने भारत के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मुरलीकांत पेटकर का किरदार निभाया। इसके लिए कार्तिक ने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया था। इस फिल्म का निर्देशन कबीर खान ने किया।

बस 3 दिन बाकी : जन नेता का दमदार नया पोस्टर आउट, एडवांस बुकिंग को मिला शानदार रिस्पॉन्स

मुंबई ग्रैंड वर्ल्डवाइड रिलीज़ में अब बस तीन दिन बाकी हैं और इसी बीच 'जन नायगन' (हिंदी में 'जन नेता') के मेकर्स ने फिल्म का एक धांसू नया पोस्टर रिलीज़ कर एक्साइटमेंट को डबल कर दिया है। साल की सबसे बड़ी सिनेमैटिक रिलीज़ में शुमार इस फिल्म को लेकर फैंस का जोश पहले ही हाई है, खासकर इसलिए क्योंकि यह बड़े पर्दे पर थलपति विजय की आखिरी फिल्म होने जा रही है।

नए पोस्टर में थलपति विजय एक रौबदार पुलिस ऑफिसर के अवतार में फुल स्वैग और पावर के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं, बॉबी देओल की इंटेंस मौजूदगी कहानी में टकराव का तड़का लगाते हुए एक जबरदस्त फेस-ऑफ की ओर इशारा करती है। पोस्टर की पहली झलक ही साफ कर देती है कि फिल्म में एक्शन, स्केल और इंटेंसिटी का जबरदस्त डोज़ मिलने वाला है। फिल्म को लेकर बढ़ती दीवानगी के बीच 'जन नायगन'/'जन नेता' की एडवांस बुकिंग भी शानदार अंदाज में शुरू हो चुकी है।

देशभर में फैंस तेजी से टिकट बुक कर रहे हैं और शुरुआती रिस्पॉन्स बता रहा है कि थलपति विजय को आखिरी बार बड़े पर्दे पर देखने का क्रेज किस कदर सिर चढ़कर बोल रहा है। एच. विनोथ के निर्देशन में बनी इस फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है। 'जन नायगन' (हिंदी में 'जन नेता') को केवीएन प्रोडक्शंस के बैनर तले वेंकट के. नारायण ने ज़ी स्टूडियोज़ के सहयोग से प्रोड्यूस किया है। अब जब रिलीज़ में सिर्फ तीन दिन बाकी हैं, एक्साइटमेंट हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही है।

फैंस भी थलपति विजय की इस आखिरी सिनेमैटिक आउटिंग को बड़े पर्दे पर एक यादगार जश्न की तरह सेलिब्रेट करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जिसके बाद वह अपनी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। 'जन नायगन' (हिंदी में 'जन नेता') 23 जुलाई को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित।
शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com